● वर्ष-2
● अंक-146
रायपुर, रविवार
05 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 05 फरवरी रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पत्र का अगला अंक 07 फरवरी मंगलवार को प्रकाशित होगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटेंगे 15 हजार नेता

राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में

■ **लोकसभा चुनावों की बनेगी रणनीति**

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा हैं। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। इस लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान ने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन और स्वागत समिति की घोषणा कर दी है। इस स्वागत समिति में प्रदेश के 114 नेताओं का शामिल किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जबकि सीएम को समिति का सह अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। जबकि आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार से अलग सुर रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को इस समिति का हिस्सा बनाया गया है। अतिथियों के आने-जाने की जिम्मेदारी वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, रुकने-ठहरने की व्यवस्था मंत्री शिवकुमार डहरिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामगोपाल संभालेंगे। यह समिति कांग्रेस हाई कमान ने खुद तय की है, ताकि तमाम आयोजनों की निगरानी की जा सके।

इसके अलावा आयोजन समिति का अध्यक्ष पवन कुमार बंसल को बनाया गया है। तारिक अनवर इसके संयोजक होंगे। वहीं कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सभी 47 नेता इसके सदस्य होंगे। इस समिति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एके एंटनी, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं। आयोजन समिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी विशेष आमंत्रित के तौर पर शामिल किया गया है।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा। इस तीन दिवसीय महाधिवेशन के दौरान देश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नये विचारों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी 2023 में होने वाला है। इस आयोजन के लिए नवा रायपुर के मेला स्थल को चुना गया है। यह वही जगह है जहां पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौर में राज्योत्सव का आयोजन होता रहा है। इस जगह पर अधिवेशन के लिए टेंट पर पूरा शहर बसाया जा रहा है। वहीं मुख्य मंच की भी साज-सज्जा जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो बार तैयारियों का जायजा ले चुकी हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को पहले ही एतिहासिक मौका बता चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दो समितियों के गठन का आदेश जारी किया। इसमें स्वागत समिति में केवल छत्तीसगढ़ के 114 नेताओं का नाम है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल, सभी सांसदों, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं का नाम शामिल किया गया है। इस अधिवेशन मे देशभर के करीब 15 हजार नेताओं के छत्तीसगढ़ पहुंचने की उम्मीद है। इन नेताओं की मेहमान नवाजी के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खाने, पीने ठहरने, ट्रांसपोर्ट अन्य व्यवस्थाओं के लिए छह हजार कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अधिवेशन अहम

आगामी लोकसभा और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये अधिवेशन अहम माना जा रहा है। सबसे पहले तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है, उनमें दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पार्टी इन दोनों राज्यों में वापसी के अलावा बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने की रणनीति पर बैठक में चर्चा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को अधिकांश सीटों पर उतारने जैसा फैसला किया था, इसी तरह कांग्रेस अधिवेशन में नई रणनीति पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी इस पर भी इस अधिवेशन में चर्चा हो सकती है।

मनरेगा में किए भ्रष्टाचार का हिसाब दें भूपेश- अरुण साव

■ **मुख्यमंत्री के आरोप पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पलटवार**

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट में मनरेगा में कटौती का आरोप लगाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल यह बताएं कि मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार किया गया है? छत्तीसगढ़ में कितने फर्जी भुगतान किए गए हैं और मनरेगा की राशि का कहां-कहां किस किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है? मनरेगा की राशि अन्य प्रयोजनों पर खर्च की गई है अथवा नहीं?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां वहां की बातें करने की बजाय सबसे पहले तो यह बताएं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की 10 हजार करोड़ की राशि क्यों लौटाई गई? तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने स्वयं यह बताया था कि 10 हजार करोड़ मिलने से छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों को कितना काम मिलता और ऐसा न होने की वजह से छत्तीसगढ़ का कितना नुकसान हुआ है। भूपेश बघेल को यह भी बताना चाहिए की तत्कालीन पंचायत मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देते समय जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब अब तक क्यों नहीं दे पाए हैं।

श्री साव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में प्रधानमंत्री आवास का बजट 66 प्रतिशत बढ़ाया है भूपेश सरकार ने न केवल 16 लाख लोगो से मकान छीना है बल्कि इसका निर्माण करने वाले भी हजारों मजदूरों का हक मारकर उनसे रोटी छीनी है। असली मजदूर विरोधी कांग्रेस है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास रोककर दे दिया है।

एएमयू में छात्रों ने फिर लगाए अल्लाहु अकबर के नारे

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कई छात्रों ने शुक्रवार की नमाज के बाद अल्लाहु अकबर और नारा-ए-तकबीर के नारे लगाए। वे राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की वर्दी पहने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अल्लाह हो अकबर का नारा लगाने के लिए एक साथी छात्र वाहिदुज्जमा के निलंबन का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने अपने साथी छात्र का निलंबन रद्द करने की मांग की। इस संबंध में छात्रों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यू-सीरीज़ में दिखाए गए तथ्य सही थे। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर एएमयू में अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने वाले छात्र को एएमयू प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने एक बयान में कहा कि कैंपस में बीबीसी फिल्म से जुड़े पोस्टर बाहरी लोगों ने लगाए थे न कि उन्होंने। विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान धार्मिक नारे लगाने वाले एक मुस्लिम छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया और पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। एनसीसी कैडेट के नारे लगाने का वीडियो अब वायरल हो गया है। हालांकि बाद में कुछ और वीडियो वायरल हुए, जिनमें हिंदू समुदाय के छात्र धार्मिक नारे भी लगा रहे थे।

योग गुरु रामदेव ने मुस्लिमों पर साधा निशाना

बाड़मेर। योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए मुस्लिमों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू लड़कियों का अपहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों धर्म इस्लाम व ईसाई पर धर्मांतरण का जुनून सवार था, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा जीवन जीना सिखाता है। रामदेव ने बृहस्पतिवार को बाड़मेर में संतों की एक सभा में कहा, अब कोई मुसलमान से पूछे कि आपका धर्म क्या कहता है। वह कहेगा कि सब पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मन में आए वह करो, चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो,वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं।

रायपुर। स्काउट का नेशनल जम्बूरी छत्तीसगढ़ में भी होगा। शनिवार को जिला स्काउट संघ की रैली में स्काउट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काउट आंदोलन ब्रिटेन में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य मित्रता भाव और सेवा है। भारतीय संस्कृति भी वसुधैव कुटुम्बकम के विचार पर है और इस तरह से दोनों विचार एक जैसे भातृत्व और सेवा के विचार हैं।

प्रमुख समाचार

अडानी मामला: पहले भी वापस लिए गए हैं एफपीओ, देश की छवि, स्थिति प्रभावित नहीं हुई- वित्त मंत्री

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट के बाद हितधारकों के साथ बातचीत के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अडानी संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बुधवार शाम अचानक ?20,000 करोड़ के अपने एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) को वापस लेने से देश के मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल और प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एफपीओ वापसी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कितनी बार इस देश से एफपीओ वापस नहीं लिया गया है और कितनी बार भारत की छवि इसके कारण खराब हुई है और कितनी बार एफपीओ वापस नहीं आए हैं? अडानी विवाद और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमण ने कहा कि इसलिए नियामक अपना काम करेंगे। दरअसल, प्रमुख स्थिति में बाजार को अच्छी तरह से विनियमित रखने के लिए, सेबी प्राधिकरण है और उसके पास उस प्रमुख स्थिति को बरकरार रखने का साधन है।

राहुल की पीएम मोदी से गुहार, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताएं दूर करने की अपील

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं तथा सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू-कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा, ''आतंकियों द्वारा हाल में कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों की लगातार चुन-चुनकर की जा रही हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।'' कांग्रेस नेता के अनुसार, इन हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है।

कर्नाटक में मतदाताओं को रिझाने के लिए बांटे जा रहे प्रेशर कूकर, डिनर सेट

बेंगलुरु। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों में डिनर सेट, प्रेशर कूकर, डिजिटल घड़ियां और अन्य उपहार शामिल हैं। कुछ नेताओं को अपने मतदाताओं की तीर्थयात्रा का खर्च उठाते हुए देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति, कर्नाटक का मंजूनाथ स्वामी मंदिर और महाराष्ट्र का शिरडी मतदाताओं के पसंदीदा तीर्थस्थलों में शामिल है। हाल में बगलकोट जिले में एक प्रमुख नेता की तस्वीर वाली डिजिटल घड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एक निवासी ने बताया कि बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को डिनर सेट बांटे गए हैं। एक महिला ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया, ''मुझे दोपहर को एक कॉल आया और डिनर सेट ले जाने के लिए कहा गया। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब मैं वहां गई तो पाया कि वे सच में डिनर सेट बांट रहे थे।'' शहर के एक अन्य क्षेत्र में एक पूर्व मंत्री ने कथित तौर पर मतदाताओं के एक वर्ग के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया।

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर

नई दिल्ली। सरकार ने शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिथल (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार (मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) नियुक्ति की अनुशंसा की थी। सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 2 फरवरी को नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी और नामों को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था।

भारत में बनी आई ड्रॉप से अमेरिका में चली हुई कई लोगों की आंखों की रोशनी

चेन्नई। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर अमेरिका में दी गई अपनी दवा की पूरी खेप को वापस मांग रहा है। कंपनी पर आरोप है कि उसकी दवा डालने से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि एक की मौत हो गई। इस खबर के बाद केंद्रीय एजेंसी भी हरकत में आ गई। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन और तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर पर देर रात छापा मारा। ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर, चेन्नई से 40 किमी दक्षिण में स्थित है। 'दोनों दलों में तीन-तीन अधिकारी हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने एक बयान में कहा कि चेन्नई स्थित कंपनी इजरीकेयर, एलएलसी और डेलसैम फार्मा द्वारा उपभोक्ता स्तर पर वितरित की जा रही 'आर्टिफिशियल टियर्स ल्यूब्रीकैंट' आई ड्रॉप को संभावित संदूषण के चलते वापस ले रही है। बयान में कहा गया है कि आज की तारीख तक, आंखों में संक्रमण, स्थायी रूप से आंखों की रोशनी चले जाने और रुकधारा संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होने सहित आंखों को नुकसान पहुंचने के 55 मामले सामने आ चुके हैं।

साज़िशों के सायें में अंधेरे पलने लगे है !

गोपाल सामंतो

लगभग पूरे विश्व में कोविड वायरस अब हवा में नहीं है, पर उसका दंश अभी भी मौजूद है और हर मौक़े में अपना अस्तित्व दिखा रहा है। एक समय कहावत थी की ब्रिटेन में कभी सूरज नहीं ढलता आज उस ग्रेट ब्रिटेन में भी आर्थिक संकट इतनी गहरा गई है की पिछले एक साल में तीन प्रधान मंत्री बदल दिये गए है। जर्मनी जैसे देश में ऊर्जा संकट के चलते लोग सड़कों पर आंदोलनरत है। सारा यूरोप पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट और यूक्रेन संकट के सायें में आर्थिक संकट से उबरने की घोर कोशिश में लगा हुआ है।

एशिया भी इन संकटों से अछूता नहीं है और वैश्विक मंदी से जूझ रहा है , श्रीलंका से आयी तस्वीरें अभी भी ज़हन में ताज़ी है जहां राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। पाकिस्तान का तो क्या कहना, नए प्रधान मंत्री शाहबाज़ शरीफ़ एक हाथ में अपनी न्यूक्लियर ताकत और दूसरे हाथ में कटोरा लिए घूम रहे है और कभी बाढ़ के नाम पर या कोविड के नाम पर आर्थिक मदद माँगते टीवी और यूट्यूब में छाये हुए है। कुछ सालों पहले जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत को पीछे छोड़ने वाली बांग्लादेश भी आईएमएफ़ से बेल आउट पैकेज ले चुकी है और ज़बरदस्त आर्थिक तनाव के दौर से गुज़र रही है। दुनिया का कारखाना कहलाने वाली चायना से ख़बरें तो बाहर आ नहीं पाती है लेकिन यह तो साबित हो गया की इस फ़ैक्ट्री में ताला लटक चुका है। कोविड के कारण विश्व के लगभग सभी बड़े ब्रांड्स ने चायना से नाता तोड़ लिया है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सस्ते मैनपावर के कारण अपना रुख़ ताइवान और भारत के तरफ़ मोड़ चुके है। चायना इस कारण बौखलाहट में है लेकिन कोविड से उबरने में पूरी तरह से नाकाम और लाचार दिख रहा है इसलिए सामरिक रूप से जवाब देने में नाक़ाबिल है। कहते है ना खुद फेल हो जाओ तो बुरा लगता है लेकिन दोस्त या पड़ोसी अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो बुरा लगना और कई गुणा बढ़ जाता है। बस यही सिंड्रोम चायना - भारत के रिश्तों पर भी लागू हो गया, इस वजह से पिछले एक साल में चायना ने ऐसा कोई मौक़ा नहीं गवाया

जहां भारत को या भारत में चल रहे वर्तमान सरकार को बदनाम किया जा सके जिससे भारत की आर्थिक तरक़्क़ी रुक जाए। हिंडनबर्ग एक छोटे से जर्मन गाँव का नाम है जिसने तब पहली बार प्रसिद्धि पायी जब 1937 में विश्व का पहला हिंडनबर्ग नामक एयरशिप दुर्घटनाग्रस्त हुई। लेकिन इस वाक्ये को शायद बहुत कम भारतीय जानते होंगे। देश का बजट अगर थोड़े दिन बाद आता तो शायद हम आम भारतीय अभी भी हिंडनबर्ग शब्द से अनजान रहते, लेकिन संयोग देखिये बजट 2023 और हिंडनबर्ग दोनों एक साथ हमारे जीवन में एक दो दिन के अंतराल में घर बसाने आ पहुँचे।

देश में पहली बार 45 लाख करोड़ का विशाल बजट प्रस्तुत हुआ लेकिन वो गुमनामी में कही खो गया क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर्स का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा थी। अड़ानी देश नहीं है लेकिन हमने मान लिया की अड़ानी ही भारत की अर्थ व्यवस्था है। 9 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया सड़कों के विकास के लिए लेकिन यह बात हमें इतना आकर्षित नहीं कर रहा है जितना की अड़ानी एंटरप्राइज़ के गिरते शेयर प्राइस, भले ही आज तक हमने एक पैसा भी शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट किया हो। इनकम टैक्स के स्लैब में बड़ा फ़र्क़ आया लेकिन कोई बात इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है तो सिर्फ़ अड़ानी के वर्चुअल पतन की और उससे सरकार के रिश्तों की, होनी भी चाहिए क्योंकि हम साज़िश में फ़स चुके है। ऐसा हमारे साथ पहली बार भी नहीं हो रहा है यह खेल हमारे साथ 2010-11 में भी खेला जा चुका है, जिससे उबरने में हमें दस साल लग गए। 2009-10 वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट चायना को को टक्कर देते हुए 8.5 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, उस वर्ष चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट केवल हमसे दो प्रतिशत ऊपर 10.64 पर थी। फिर आया दो अनुमानित घोटालों की खबर वो थी 2% स्पेक्ट्रम आवंटन का 1.76 लाख करोड़ का अनुमानित घोटाला और कोल ब्लॉक आवंटन का 1.86 लाख करोड़ का अनुमानित घोटाला। रिजल्ट देखिये अगले साल भारत का ग्रोथ रेट पहुँच गया 5.24 प्रतिशत पर और चायना का रहा 9.65 प्रतिशत पर, चायना में आयी गिरावट बहुत मामूली और नेचुरल थी। लेकिन भारत में आयी गिरावट का दोषी कौन था, चायना जिसने इस साज़िश को अंजाम दिया या हम जैसे आम नागरिक जिसने उस साज़िश को हर चौक चौराहे में हवा दी।

आर्थिक विषय बहुत जटिल होते है और प्रक्रियागत ढंग से बहुत पेचीदा भी, लेकिन आज डिजिटल भारत का दुर्भाग्य देखिए हाई स्कूल तक भी जिसने पढ़ाई नहीं की वो भी व्हाट्सएप्प में आये मैसेजों के बल पर अड़ानी का भविष्य तय करने में लग गया है। क्योंकि इस बार 2021 भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना के 8.11 प्रतिशत को पीछे छोड़ते हुए 8.95 प्रतिशत तक पहुँच चूँका है। आम आदमियों को तो छोड़िए पत्रकार और बुद्धिजीवी भी इस साज़िश में जकड़ लिए गये है, उन्हें अब तुलनात्मक स्टडी से सरोकार नहीं रहा है अब उनमे भी रिजल्ट तक पहुँचने की आतुरता इस कद्र बढ़ गई है की वो अपनी सामाजिक दायित्व को भूल गए है। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का डिफेंस बजट आज विश्व में तीसरे पायदान तक पहुँच चुका है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी , रशिया जैसे विकसित देश आज डिफेंस बजट में भारत से कही पीछे चले गये है। अब भारत विकासशील देश के टैग को छोड़ विकसित देशों के पंक्ति पर पहुँच गया है और इसका जीता जागता उदाहरण है ज-20 की मेजबानी करना।

ऐसे में छोटा सा एक हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की सोची समझी साज़िश हमारे आर्थिक ताने बाने को खत्म तो नहीं कर सकती है परंतु क्षति जरूर पहुँचा सकती है। तटस्थता के साथ इस विषय पर सोच विचार और एनालिसिस के बाद ही अपना तर्क रखना चाहिए, क्योंकि आप वो पीढ़ी है जो बदलते भारत की गवाही देंगे भविष्य में और आपसे उम्मीद रखी जाएगी की आप अपने ज़िम्मेदारी को बिना राजनैतिक सोच या पूर्वाग्रह के साथ निभायेंगे।

विश्व स्तर पर भारत को सशक्त एवं समृद्ध बनाने वाला बजट : राजेन्द्र गोलछा

नगरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट विश्व स्तर पर भारत को सशक्त एवं समृद्ध बनाने वाला बजट है। इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिली है टैक्स की सीमा को पांच लाख से 7 लाख किया गया है इसी के साथ ही इस बजट से युवा,गरीब,मजदूर,व्यवसायी,महिलाओं सहित सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट में स्वास्थ्य,शिक्षा सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। युवाओं को रोजगार मिले इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। फाइनेंशियल सेक्टर और युवाओं का ध्यान रखा गया है।गोवर्धन योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66फीसदी बढ़ा कर 79 हजार करोड़ किया गया है।कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज योजना को बढ़ाया गया है।बेरोजगार युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है कृषि ऋण को लक्ष्य को बढ़ाया गया है कृषि के क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एकलव्य एवं मॉडल स्कूलों में 38 हजार अध्यापकों एवं स्टाफकी नियुक्ति की जाएगी इससे आदिवासी क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा।।157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी।

राज्य सरकार पंचायतों का हक छीन रही : महेन्द्र नेताम

नगरी। छत्तीसगढ़ में भले ही गांवों की दशा सुधारने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगातार पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मुनईकेरा के सरपंच महेन्द्र नेताम ने आरोप लगाया कि अन्य विभाग ग्राम पंचायत के कार्यों को अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिये दे रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत का हक छीना जा रहा है। उन्होंने मांग किया है कि शाला भवन निर्माण, शाला मरम्मत के कार्य, सामुदायिक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य 50लाख से कम के कार्य पंचायतों को दिया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो मनरेगा के कार्यों को भी ठेका पद्धति से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा किया है कि पंचायत को 50 लाख तक कार्य कराया जाना है। लेकिन उनके कई विभाग द्वारा 50 लाख से कम तक कार्य को पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत को 50 लाख तक के काम कराने का अधिकार की बात करने वाले पंचायत का निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। पंचायत के कार्यकाल लगभग 3 साल हो गया है विगत दो साल से कोरोना के कारण व शासन से कोई फण्ड नहीं मिलने से पंचायतों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है।

प्रेमलता ने क्षेत्रवासियों को कर्णेश्वर मेला की दी बधाई

नगरी। वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं जिला मंत्री भाजपा प्रेमलता नागवंशी ने माघ पूर्णिमा व कर्णेश्वर मेला की सिहावा विधानसभा क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। श्रीमती नागवंशी ने कहा कि सोमवंशी राजाओं द्वारा निर्मित शिव मंदिर जिसे कर्णेश्वर महादेव मंदिर के नाम से सब जानते है। जहां प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पांच दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां प्रतिदिन पूरे प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा से श्रद्धालु कर्णेश्वर महादेव का दर्शन करने आते है। वहीं मंदिर से लगे महानदी व बालका नदी के संगम पर श्रद्धालु माघ पूर्णिमा पर डुबकी लगाते है।

अवैध खनिज परिवहन करते 6 हाइवा पकड़ाए

■ खनिज सहित माइनिंग एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, डेढ़ लाख रुपए से अधिक का जुर्माना

पाटन। खनिज महकमा की टीम ने शुक्रवार.को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर जांच की। इस दौरान अवैध रूप से खनिज परिवहन कर रहे 6 हाईवा पकड़े गए इन सभी को खनिज सहित जप्त कर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनिज परिवहन कर रहे वाहनों पर ढेढ़ लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक भरत बंजारे के नेतृत्व में एवं टीम शामिल सहयोगी टी एस उमरे एवं खनिज विभाग के सतीश देवांगन व अन्य वे अलग अलग जगहों पर दबिश देकर खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की जांच के दौरान पाटन क्षेत्र के जामगाव आर किसान चौक पर एक हाईवा एवं एक अन्य हाईवा में गिट्टी का बिना रॉयल्टी पर्ची का परिवहन करते पाया गया।

जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन करते पकड़े गए वाहनों में सीजी07 बी सी 8659, सीजी 07 सीजी 3280, सीजी 07 बीई 1728, सीजी 14 एमडी 5826, सीजी 07 बीई 9920 एवं सीजी 07 बीवाई 5508 शामिल है।खनिज परिवहन करते पकड़ाए। इन्हें नेवई व उतई थाने के सुपुर्दगी में दिया गया है। खनिज निरीक्षक भरत बजारे का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खनिज विभाग की टीम की लगातार कार्रवाई कर रही है। आज पकड़े गए वाहनों में से 2 में रेत एवं 4 में अवैध रूप से चूना पत्थर का परिवहन करते हुए जामगांव आर थाने में खड़ी कराई गई है। इसी तरह से दुर्ग क्षेत्र के ग्राम मंचादुर के पास दो हाईवा में बिना रॉयल्टी के गिट्टी का परिवहन करना पाया गया, इन्हें मंचादुर चौकी में खड़ी कराई गई है। इसके अलावा नेवई और उतई क्षेत्र में भी दो हाईवा अवैध किया जा रहा था।

व्यापारियों को परेशान कर रहे जिपं सीईओ कोरबा

जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिखा पत्र

कोरबा। ग्राम पंचायत रजगामार में सरपंच और सचिव पर लाखों की शासकीय राशि के गबन के गम्भीर आरोपों की जांच चल रही है। इसी बीच कोरबा जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर पर व्यापारियों सामग्री आपूर्तिकर्ता वेंडरों को नोटिस देकर बेवजह परेशान करने का आरोप लगा है। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कोरबा के अध्यक्ष योगेश जैन ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर व्यापारियों को बेवजह तंग नहीं करने की ताकीद दी है।

शुक्रवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत रजगामार में सरपंच. सचिव द्वारा कथित घपला किया गया है। उसके एवज में आपके द्वारा व्यापारियों पत्र क्रमांक 163 दिनांक 31 जनवरी के माध्यम से नोटिस दिया गया है। इस संदर्भ में 2 फरवरी को प्रात: 11 से 02 बजे तक व्यापारियों को जिला पंचायत में बुलाकर पूछताछ की गई है। पत्र में कहा गया है कि बेवजह व्यापारियों को तंग न करें। आपके सरपंच .सचिव व अन्य कर्मचारियों को तलब करें। उन्हीं से पूछताछ करें।

यहां उल्लेखनीय है कि गृह जिले में पदस्थ जिला पंचायत सी ई ओ की कार्यशैली प्रारम्भ से संदिग्ध है। आवश्यकता तो जिला पंचायत सी ई ओ के कार्यकाल की जांच की भी है। क्या कलेक्टर, रजगामार के सरपंच सचिव के साथ जिला पंचायत सी ई ओ के कार्यकाल की भी जांच कराएंगे।

कर्मचारियों में बचत की भावना बढ़ावा देने के लिए धारा 80 सी का लिमिट बढ़ाना था : फेडरेशन

■ धारा 80 सी अंतर्गत छूट को नज़रंदाज़ करने की नीति से कर्मचारी अपने वेतन से बचत करने की मानसिकता से विमुख होगा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,उप प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर,विष्णु सिंह राजपूत, प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, महामंत्री आर डी तिवारी, बी एल शर्मा,राकेश साहू,संगठन मंत्री के आर देशमुख एवं प्रवक्ता विधुशेखर झा ने केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 सी अंतर्गत छूट की महत्ता को दरकिनार करना कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए घातक साबित होगा ।

कर्मचारी अपने वेतन से बचत करने की मानसिकता से विमुख होगा। निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा से देश की अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 सी में 1.5 लाख रुपयों तक इन्वेस्ट की गई राशि पर इनकम में छूट मिलता है। इस लिमिट को बढ़ाने से देश के लाखों कर्मचारी ज्यादा निवेश करता जोकि देश की विकास में सहायक होता। केंद्रीय बजट 2016 से 2023 तक इसमें वृध्दि नहीं हुआ है। फेडरेशन के कहना है कि कर्मचारियों से वार्षिक ग्रॉस(सकल) वेतन पर इनकम टैक्स लिया जाता है। जबकि 80 सी के कटौतियों के बाद उसे वह वेतन वास्तविक में नहीं मिलता है। इस दिशा में सुधार अपेक्षित था। केंद्रीय बजट 2023 में 7 लाख वार्षिक आय पर टैक्स नहीं लगने का खुलासा फेडरेशन ने किया है। यदि कर्मचारी का वार्षिक आय 7.5 लाख रुपये है। अब सकल वेतन से मानक कमी 50000 के बाद आय 7 लाख रुपये होगा। बजट 23 के टैक्स स्लैब के अनुसार 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। शेष 4 लाख में 3 लाख पर 5 % दर से 15000 टैक्स तथा शेष 100000 पर 10 % दर से ? 10000 टैक्स कुल 25000 टैक्स आयेगा। संभवत: इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87 A में 25000 का छूट देकर टैक्स को शून्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये तक के वार्षिक आय पर 12500 का छूट धारा 87 (ए) में प्रावधानित कर टैक्स को शून्य किया गया था। फेडरेशन का कहना है कि यदि 1 का वृध्दि हुआ तो कर्मचारी को 4 % अधिभार सहित 26000 टैक्स भुगतान करना होगा। फेडरेशन ने बताया कि केंद्र में जुलाई 22 के स्थिति में 38% महँगाई भत्ता है। जोकि माह जनवरी 23 में, 132.3 (अनुमानित) के आधार पर न्यूनतम 4 % वृध्दि के साथ 42 % संभावित है। जुलाई 2023 में यदि 3 % वृध्दि महँगाई भत्ता में होता है तो 7 % के वृध्दि के साथ 1 का वृद्धि निश्चित है। 18 वीं लोकसभा चुनाव मई 2024 या इससे से पहले संभावित है। जिसके दृष्टिगत महँगाई भत्ता में जनवरी 2024 से पुन: 4 % वृध्दि हो सकता है। फेडरेशन के कहना है कि महँगाई भत्ता में वृद्धि के साथ टैक्स में वृद्धि होगा। बजट 2023 में प्रस्तावित नये स्लैब में टैक्स निर्धारण में कमी परिलक्षित हो रहा है। लेकिन सुपर रिच क्लास को सर्वाधिक लाभ मिला है। जितना अधिक आमदनी, उतना अधिक टैक्स बचत होता दिख रहा है।

बीएसएनएल दफ्तर में गाड़ी लगाने का झांसा देकर ठगी

■ एफआईआर के बाद 24 घंटे के अंदर पकड़ाया

भिलाई। बीएसएनएल दफ्तर में वाहन किराए में लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने एफआईआर के बाद 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरापी को पुलिस ने शंकर नगर छावनी से गिरफ्तार किया है। आरपी के कब्जे से पुलिस ले 600 रुपए नगदी व एक लाख 15 हजार रुपए कीमत का मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपी के खिलाफदुर्ग पुलिस द्वारा धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई है।

बता दें एक फरवरी को देवबलौदा चरोदा निवासी यमन नायक ने दुर्ग कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि मोबइल नंबर 6267608601 के धारक ने कॉल कर उसकी गाड़ी को बीएसएनएल दफ्तर में किराए पर लगवाने की बात कही थी। इसके एवज में महीना 40 हजार रुपए किराए मिलने का झांसा दिया था। उसके झांसे में आकर प्रार्थी कलेक्टोरेट परिसर में उससे मिला। 2 जनवरी 2023 को कलेक्टर परिसर दुर्ग में वह व्यक्ति आया यमन नायक की गाड़ी के कागज, ड्राईविंग लायसेन्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क 6500 रुपए के साथ वाहन की फेटो दिखाने के लिए मोबाईल लेकर गया था। मोबाइल सेमसंग कंपनी था और उसकी कीमत एक लाख 15 हजार रुपए है।

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। जो मोबाइल नंबर प्रार्थी ने बताया वह भी दूसरे के पते पर दर्ज था जिससे आरोपी की तलाश नहीं हो पा रही थी। इसके बाद साइबर टीम की सहायता से आसपास के सीसी टीवी फूटेज खंगाले गए जिसमें प्रार्थी द्वारा बताए गए हुलिए वाला शख्स दिखाई दिया। इसके पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया। इस दौरान दुर्ग कोतवाली पता चला कि शंकर नगर छावनी में इसी हुलिए से मिलता जुलता चेहरा नजर आया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शहीद महेन्द्र कर्मा विवि में दो दिनी अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी 10 से

जगदलपुर। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय एवं गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विवि बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में 10 फरवरी से दो दिवसीय अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य बहुआयामी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपर्क विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित है। इस संगोष्ठी में शोध पत्र का वाचन एवं प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा संगोष्ठी में भाग लेने, शोध पत्र का वाचन/ प्रेजेंटेशन करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई सूचना एवं विषय वस्तु की जानकारी शहीद महेन्द्र कर्मा विवि बस्तर एवं गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय बिलासपुर के वेबसाईट एवं समन्वयक डॉ.आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन शाला से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठी में भाग लेने पर पंजीयन शुल्क एवं आवासीय व्यवस्था का व्यय भार प्रतिभागियों को वहन नहीं करना होगा।

बीएसपी ने मिराज सिनेमा सील किया

भिलाई। 6 करोड़ 92 लाख रुपये का राजस्व भुगतान न करने एवं बीएसपी के संपदा न्यायालय में हारने के बावजूद मिराज सिनेमा संचालित किया जा रहा था। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग द्वारा शनिवार को मिराज सिनेमा को सील कर दिया गया। इसके अलावा परिसर में ही संचालित जिम को भी बंद करा दिया। बीएसपी टाउनशिप के सिविक सेंटर में मिराज सिनेमा संचालित है इसके लिए जमीन बीएसपी द्वारा लीज पर दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को मिराज सिनेमा के संचालक से 6 करोड़ 92 लाख राजस्व वसूलना है इसके अलावा नौ लाख का भुगतान और अतिरिक्त वसूला जाना है। इस मामले को लेकर मिराज सिनेमा के संचालक द्वारा कोर्ट में प्रकरण दायर किया गया। बीएसपी के संपदा न्यायालय में मिराज सिनेमा प्रबंधन केस हार चुका है। नगर सेवा विभाग के तोड़फोड़ विभाग द्वारा आज सुबह कार्यपालक दंडाधिकारी एवं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिराज सिनेमा को सील कर दिया गया। सील की कार्रवाई के दौरान तोडफ़ोड़ दस्ता का भारी अमला मौजूद था।

जिला पुरातत्व संघ की बैठक 9 फरवरी को

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा की अध्यक्षता में जिला पुरातत्व संघ की बैठक 09 फरवरी 2023 को दोपहर 02:00 बजे कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में जिला पुरातत्व संघ संग्रहालय कोरबा को मय स्टाफसहित संस्कृति एवं पुरातत्व संग्रहालय विभाग रायपुर को सौंपने के लिए पूर्व बैठकों पर प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा, संग्रहालय भवन के उन्नयन कार्य एवं संग्रहालय को आकर्षक बनाने पर चर्चा, संग्रहालय में संगोष्ठियों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम निर्माण एवं अतिरिक्त कक्ष में संगीत डान्स, पेंटिंग गतिविधि के लिए उपयोग पर चर्चा, मार्गदर्शक के वेतन विसंगति दूर करने एवं नियमितिकरण करने पर चर्चा, संग्रहालय के आर्ट गैलरी पर बाहरी कला संघो एवं कलाकारो को प्रदर्शनी लगवाने की अनुमति देने पर चर्चा एवं अध्यक्ष संस्कृति एवं जिला पुरातत्व संघ कोरबा के निर्देशानुसार अन्य बिंदु पर चर्चा की जाएगी।

डुंडेरा स्कूल में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ

रिसाली। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डुंडेरा में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि प्रदेश कांग्रेस महासचिव जितेंद्र साहू थे।विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम रिसाली के सभापति केशव बंजोर,एमआईसी सदस्य सनिर साहू, एल्डरमेन तरुण बंजारे, पार्षद रोहित धनकर, जाहिर अब्बास, अनिल देशमुख शामिल हुए।इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमो की भी प्रस्तुति दी गयी में साथ ही एनसीसी में विजयी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया।मुख्यातिथि जितेंद्र साहू ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहा की अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रुप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।कार्यक्रमों से छात्र-छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है।कार्यक्रम में शाला विकास समिति के अध्यक्ष धनेश मानिकपुरी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी।

भैंसमा रेलवे फाटक 6 और 7 फरवरी को रहेगा बंद

कोरबा। भैंसमा (उरगा-कोरबा) में स्थित समपार रेलवे फाटक 06 एवं 07 फरवरी तथा इमलीछापर (कुसमुण्डा) रेलवे फाटक 06 फरवरी को जरूरी मरम्मत काम के कारण सड़क मार्ग के यातायात के लिए बंद रखा जायेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसके लिए सूचना भी जारी कर दी है। भैंसमा (उरगा-कोरबा) में स्थित समपार रेलवे फाटक क्रमांक सीजी 20 कि.मी. 694/29-31 डाउनलाईन 06 एवं 07 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक आवागमन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान भारी वाहन के अलावा छोटे वाहन परिवर्तित मार्ग सीजी 23 (रिंगरोड गेट) कि.मी. 697/20-22 से यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार 06 फरवरी को इमलीछापर (कुसमुण्डा) सीजी क्रमांक 32 कि.मी. 711/2-3 में स्थित मानव सहित समपार फाटक में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 तक ओवर हाऊलिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके लिए उक्त समयावधि में फाटक को बंद रखा जाएगा। इस अवधि में नागरिकगण परिवर्तित मार्ग शांति नगर अंडर ब्रिज से आवागमन कर सकते हैं।

महानदी नदी के संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे

■ पांच दिवसीय कर्णेश्वर मेला महोत्सव 5 से शुरू

नगरी। सिहावा में श्रृंगी ऋषि पर्वत के नीचे महानदी के तट पर छिपली पारा ग्राम पंचायत अंतर्गत देउरपारा बसा है यहाँ महानदी व बालका नदी का संगम होता है मांघ पूर्णिमा पर यहां हजारो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते है। समीप ही 11वीं शताब्दी में राजा कर्णराज द्वारा निर्मित शिव मंदिर,राम जानकी मंदिर ,नन्दी,गणेश मन्दिर,विष्णु के मंदिर है इस स्थान को लोग कर्णेश्वर धाम के नाम से जानते है कर्णेश्वर धाम मे माघ पूर्णिमा के अवसर पर 5 फरवरी से विशाल मेला का आयोजन प्रति वर्ष अनुसार किया जा रहा है। कर्णेश्वर धाम मे सोमवंशी राजाओं द्वारा निर्मित भगवान शिव एवं राम जानकी का मंदिर है।

मंदिर में लगे सोलह पंक्तियों की आयताकार भीतर शिलालेख कांकेर के सोमवंशी राजा कर्णराज के शासनकाल में शक् सम्वत 1114 में उत्कीर्ण कराया गया। शिलालेख संस्कृत भाषा के देवनागरी लिपि में लिखी गयी है शिलालेख से विदित होता है कि महाराज कर्णराज ने अपने वंश की कीर्ति को अमर बनाने के लिए कर्णेश्वर देवहद मे छह मंदिरों का निर्माण किया।

एक अपने नि संतान भाई कृष्णराज के नाम, दूसरा मंदिर प्रिय पत्नी भोपालादेवी के नाम निर्मित कराया। कर्णराज ने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना कर प्रतिष्ठा किया। कर्णराजद्वारा निर्मित मंदिर मे शिव के अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानकी मंदिर प्रमुख है।

भगवान शिव को बीस वर्ग फुट आयताकार गर्भ गृह में प्रतिष्ठित किया गया ही। गर्भगृह का शीर्ष भाग कलश युक्त है। मंदिर का अग्रभाग मंडप शैली मे बना है, जिसकी छत आठ कोडीय प्रस्तर स्तंभों पर टिकी है। मंदिर का पूरा भाग पाषाण निर्मित है। जनश्रुति है कि कांकेर के सोमवंशी राजाओं के पूर्वज जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मूल निवासी थे। सोमवंशी राजाओं ने पहले पहल नगरी मे अपनी राजधानी बनाई।

कर्णेश्वर धाम मे एक प्राचीन अमृतकुण्ड है।किवदंती ही कि इस कुंड के जल के स्नान से कोड जैसे असाध्य रोग ठीक हो जाता था। सोमवंशी राजाओ ने इसे मिट्टी से भर दिया। अमृतकुंड से लगा हुआ छोटा सरोवर मोती तालाब राजा के दो पुत्रियां सोनई-रूपई के नाम से जाना जाता है। सोनई रूपई कांकेर के राजा धर्म देव की पुत्रियाँ थी।मन्दिर परिसर में विविध देवी देवताओं की प्रतिमा है सोम वंशीय राजाओं का विजय स्तम्भ है माघपुर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु बालका व महानदी के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री बाल-बाल बचे, डिवाइडर से टकराई कार

बिलासपुर। सरगुजा विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को रायपुर से अंबिकापुर जाने के लिए निकले थे. लगभग 12:30 बिलासपुर के पहले मुंगेली जिला के नानघाट के पास उनका काफिला जैसे ही पहुंचा, उसी दौरान अचानक काफिले के सामने बाइक सवार आ गया. बाइक सवार को बचाने के लिए सिंहदेव के कार ड्राइवर ने कार को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई।

कार के टायर फटे: कार के डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से कार के एक साइड के दोनों टायर फट गए. इस हादसे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव कार में मौजूद थे. इस हादसे में किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी है. बाइक सवार को भी बचा लिया गया है।

सिंहदेव का काफ्लिा रोकना पड़ा: कार का टायर फटने की वजह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का काफ्लिा कुछ देर तक उसी जगह पर रुक गया. फिर काफ्लिे की दूसरी गाड़ी में बैठ कर स्वास्थ्य मंत्री अपने समर्थक पंकज सिंह के साथ अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। बिलासपुर प्रशासन अलर्ट: इस हादसे की जानकारी लगने पर मुंगेली और बिलासपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था और मौके पर पहुंच गया था. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अधिकारियों को अपने सुरक्षित होने और किसी के हताहत नहीं होने की बात कही है. सिंहदेव ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी की जान नहीं गई।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा ने आप मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया

नईदिल्ली। आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आने के कुछ दिनों बाद भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल के प्रमुख पद से इस्तीफे की मांग की। आप मुख्यालय के विजुअल्स में भाजपा समर्थकों को केजरीवाल चोर है जैसे नारे लगाते हुए दिखाया गया है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न धन का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। ईडी ने मामले में दायर चार्जशीट में कहा जिसमें सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ-साथ उनके करीबी विजय नायर भी आरोपी हैं। ईडी के मुताबिक, आप के सर्वे दल में शामिल स्वयंसेवकों को करीब 70 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि आप के संचार प्रभारी विजय नायर ने अभियान से संबंधित कार्य में शामिल कुछ लोगों को नकद में भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा।

भाजपा ने कर्नाटक में धर्मेंद्र प्रधान को बनाए राज्य प्रभारी

नई दिल्ली। कर्नाटक में इस साल के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को कर्नाटक में चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त कर दिया। उनके साथ तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्य में सह-प्रभारी बनाया गया है। प्रधान को पहले भी कई राज्यों में चुनावों का जिम्मा सौंपा जा चुका है। पार्टी की उम्मीद रहेगी कि वह एक कुशल नेता के रूप में राज्य में संगठन को संगठित करें और स्थानीय इकाई में आंतरिक समस्याओं को दूर करें, ताकि इस महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में पार्टी सत्ता बरकरार रखने के अधिकतम प्रयास कर सके। इसके अलावा भाजपा ने सिक्किम में पार्टी संगठन में भी फेरबदल किए हैं। सिक्किम में पार्टी ने डीआर थापा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा पार्टी के विधायक एनके सुब्बा को विधायी पार्टी लीडर बनाया गया है। विधायक डीटी लेपचा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

आजाद की पार्टी के नाम को मिली चुनाव आयोग से मंजूरी

जम्मू। अंतत: कांग्रेस से आजाद हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की नवगठित पार्टी के प्रदेश में हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए पहचान का मामला सुलझ गया है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का नाम स्वीकृत कर लिया है और पंजीकरण भी जारी कर दिया है। लगातार तीन बार नाम भिजवाने के बाद अब पार्टी को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अर्थात डीपीएपी दिया गया है। नवम्बर महीने में 13 दिनों में ही उन्हें तीसरी बार पार्टी का नाम बदलना पड़ा था। 26 नवंबर को जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से आवेदन किया गया था तो उसके प्रति दुआ की जा रही थी कि वह अब स्वीकृत हो जाए। वैसे पार्टी के भीतरी सूत्र बताते थे कि इस नाम से गुलाम नबी आजाद नाखुश हैं क्योंकि वे पार्टी के लिए छोटा नाम चाहते थे। मगर मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा है। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द पार्टी का नाम स्वीकृत हो और चुनाव चिन्ह भी मिल जाए क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट आरंभ हो चुकी है। फिलहाल पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलना बाकी है।

त्रिपुरा की रैली में गरजे असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

अगरतला। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बनमालीपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ मुगल शासकों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बाबर ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आज हमने बाबर को हटा दिया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि राम मंदिर बनाएंगे तो सांप्रदायिक विवाद होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बढ़ा है। लेकिन मोदी की तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू-मुस्लिम के बीच सौहार्द भी नहीं बिगड़ा। राम मंदिर बनने के साथ-साथ देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है।

इरोड उपचुनाव में पलानीस्वामी धड़े को भाजपा का समर्थन

चेन्नई। तमिलनाडु की इरोड विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने एआईएडीएमके के पलानीस्वामी धड़े के उम्मीदवार का समर्थन करने का एलान किया है। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि ई पलानीस्वामी के उम्मीदवार केएस थेनारुसु दो बार के विधायक हैं और विधानसभा में जाना पहचाना नाम हैं। जो जीत के लिए सही हो, हम भी ऐसा ही उम्मीदवार चाहते थे। हम ओ पनीरसेल्वम से अपील करते हैं कि वह भी ई पलानीस्वामी के उम्मीदवार का समर्थन करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि एआईएडीएम पार्टी के अंदरुनी मामलों में हमारा कोई दखल नहीं है। अन्नामलाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि ओ पनीरसेल्वम अपने उम्मीदवार को पीछे हटा लें। बता दें कि इरोड विधानसभा उपचुनाव के लिए एआईएडीएमके के दोनों धड़ों ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं।

विजय संकल्प रैली : देवघर में बोले गृहमंत्री अमित शाह

झारखंड सरकार देश में सबसे भ्रष्ट आदिवासियों के साथ कर रही अत्याचार

रांची। विजय संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने का कार्य किया है। जिनकी आय 7 लाख रुपए से कम है उनको इनकम टैक्स में छूट दी है। सरकार आदिवासी भाईयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल तैयार करेगी जिसके लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कोरोना में हमने तय किया था कि सरकार किसी भी घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी, हमने ढाई साल तक प्रति व्यक्ति-प्रति माह पांच किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया है। अब एक और साल तक हम गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि कई जगह पर किसान यूरिया भी डालते हैं और तरल यूरिया का भी छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से फसल के साथ-साथ भूमि का भी नुकसान होता है। तरल यूरिया का छिड़काव करते हैं तो इफको की गारंटी है कि उत्पाद बढ़ेगा। बाद में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने झारखण्ड के एक बड़े हिस्से को उग्रवाद और नक्सलियों से त्रस्त इलाके को मुक्त करने का काम किया है। हमने झारखण्ड में विकास की राह बनाने और नक्सलवादियों से मुक्त करने का काम किया।

अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने विकास का कोई काम नहीं किया केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। जनता अब आपको जान चुकी है और आप से हिसाब मांगती है। आदिवासी बेटियों की हत्या का जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये कोई विकास का काम नहीं करना चाहते केवल वैगनों में भर कर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये क्षेत्र साइबर क्राइम का हब बन गया है। यहां बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाकर बड़े-बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जितनी भी मदद देनी चाही... हेमंत बाबू किसी पर आगे नहीं बढ़े। चुनाव आ रहे हैं... जनता खुद हिसाब कर देगी। यहां आदिवासी बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो... शर्म करो। वोट बैंक के लालच में यहां घुसपैठिए घुसाए जा रहे हैं, वो आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं और हेमंत बाबू... मुस्कराते हुए यह सब देख रहे हैं। इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है।

अमित शाह ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों के विकास का पैसा दिल्ली के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। जनता सब जानती है... हेमंत बाबू चुनाव में आ जाओ, जनता आपको हटाने को तैयार बैठी है। मोदी की सरकार ने गरीब, आदिवासी और पिछड़ों के हित को हमेशा वरीयता दी है। आजादी के बाद पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, यह हर गरीब का सम्मान है... हर आदिवासी का सम्मान है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने रखी नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला

केंद्रीय गृह मंत्री ने देवघर में 450 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नैनो यूरिया संयंत्र और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) की टाउनशिप की आधारशिला रखी। यह भारत का पांचवां नैनो यूरिया संयंत्र होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। संयंत्र की आधारशिला रखते हुए शाह ने कहा, नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होगा और इसे पहले ही पांच देशों को निर्यात किया जा रहा है।

नैनो यूरिया फसल उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है और इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग का समाधान करना है। इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा कि संयंत्र अगले साल दिसंबर में चालू होने वाला है। अवस्थी ने कहा कि संयंत्र का निर्माण 300 करोड़ रुपये की लागत से और टाउनशिप का निर्माण 150 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

वरुण गांधी की दौलत 12 गुना हुई

लगातार तीसरी बार जीते 71 सांसदों की संपत्ति में 286% हुआ इजाफा

नई दिल्ली। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी एक साल से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 2009 से 2019 के लोकसभा चुनावों के बीच लगातार तीन बार चुने गए 71 सांसदों की औसत संपत्ति 286 फीसदी बढ़ी है। इनमें प्रति सांसद की संपत्ति में औसतन 17.59 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

अध्ययन के मुताबिक, 2009 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों द्वारा मैदान में उतारे गए इन 71 दोबारा निर्वाचित सांसदों की औसत संपत्ति 6.15 करोड़ रुपये थी। लेकिन 2014 में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 16.23 करोड़ रुपए हो गई। पिछले चुनाव यानी 2019 की बात करें तो 71 सांसदों की औसत संपत्ति 23.75 करोड़ रुपये हो गई।

जिन सांसदों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है उनमें भाजपा के छह सांसद हैं। एनसीपी, शिरोमणि अकाली दल, बीजद और ढ्ढष्ठस्न से एक-एक सांसद टॉप दस में शामिल हैं। सबसे आगे बठिंडा सीट से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल हैं। दस साल में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की संपत्ति में सबसे ज्यादा 157.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 2009 में बादल की संपत्ति 60.31 करोड़ रुपये थी जो 2019 में 217.99 करोड़ रुपये हो गई।

इस सूची में दूसरा नाम शरद पवार की बेटी और बारामती सीट से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का आता है। सुले की संपत्ति 2009 में 51.53 करोड़ रुपये थी जो 2019 में बढ़कर 140.88 करोड़ रुपये हो गई। दस साल में उनकी संपत्ति में 89.35 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। संपत्ति इजाफे के मामले में तीसरा नाम पुरी सीट से बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा का आता है। दस साल में मिश्रा की संपत्ति 87.78 करोड़ रुपये बढ़ी। 2009 में उनकी संपत्ति 29.69 करोड़ रुपये थी जो 2019 में 117.47 करोड़ रुपये हो गई।

दस साल में 1124 फीसदी बढ़ी वरुण गांधी की संपत्ति

केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के सांसदों में सबसे ज्यादा संपत्ति वृद्धि पीसी मोहन की हुई है। 2009 में कर्नाटक बैंगलोर से सांसद मोहन की संपत्ति पांच करोड़ थी जो 2019 में बढ़कर 75 करोड़ हो गई। टॉप दस में पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का भी नाम है। 2009 में वरुण की संपत्ति 4.92 करोड़ थी जो 2019 में बढ़कर 60.32 करोड़ हो गई है। उनकी संपत्ति में 1124 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसी कड़ी में अन्य प्रमुख नाम सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी का है। 2009 में मेनका की संपत्ति 17 करोड़ थी जो 2019 में बढ़कर 55 करोड़ हो गई।

सबसे ज्यादा भाजपा सांसदों की बढ़ी संपत्ति, दूसरे पर कांग्रेस

लगातार तीन बार निर्वाचित सांसदों की औसत संपत्ति में वृद्धि के मामले में सबसे ज्यादा 43 भाजपा के सांसद हैं। दस साल में भाजपा के इन सांसदों की संपत्ति औसतन 15 करोड़ बढ़ी है। 2009 में इनकी औसत संपत्ति चार करोड़ थी जो 2019 में बढ़कर 20 करोड़ हो गई।

इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसके दस सांसदों की संपत्ति में औसतन दस करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 2009 में इनकी औसत संपत्ति पांच करोड़ थी जो 2019 में वृद्धि के साथ 16 करोड़ हो गई। इस कड़ी में तीसरा नाम पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का है।

71 में से इसके सात लोकसभा सदस्यों की संपत्ति में औसतन पांच करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 2009 से जीत रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की औसत संपत्ति 76 लाख थी जो 2019 में बढ़कर 5.9 करोड़ हो गई। इसी तरह दो-दो सांसदों के साथ बीजद और शिवसेना क्रमश: चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। इसके अलावा एक-एक सांसद के साथ टॉप दस में एआईएमआईएम, एआईएमआईएम , आईयूएमएल जद(यू) और एनसीपी भी हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

जिम्नास्ट दीपा करमाकर पर लगा 21 महीने का प्रतिबंध

नईदिल्ली। स्टार जिम्नास्ट और खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित दीपा कर्माकर के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। दीपा कर्माकर पर पूरे 21 महीनों का बैन लगा दिया गया है। ये बैन इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा पर लगाया है क्योंकि वो प्रतिबंधित दवा हाइजेनामाइन लेने के लिए दोषी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक दीपा कर्माकर के नमूने 11 अक्टूबर 2021 को प्रतियोगिता से बाहर लिए गए थे। इसके बाद जांच में दीपा का परीक्षण सकारात्मक आया है, जिससे वो डोपिंग की आरोपी पाई गई है। उन पर आईटीए ने 10 जुलाई 2023 तक प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि जिन दवाईयों का उपयोग दीपा ने किया है उनका उपयोग प्रतियोगिता के बाहर या अंदर रहते हुए करने पर मनाही है।

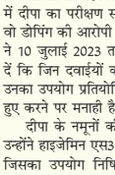

दीपा के नमूनों की जांच में सामने आया कि उन्होंने हाइजेमिन एस3 बेटा2 का उपयोग किया है, जिसका उपयोग निषिद्ध है। इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी ने इन दवाइयों को प्रतिबंधितकी श्रेणी में रखा है। अगर कोई खिलाड़ी इन दवाईयों का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगता है। जानकारी के मुताबिक दीपा पर ये टेस्ट वर्ष 2021 में किया गया था। इस संबंध में इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी ने जानकारी दी कि टेस्ट में दीपा ने सकारात्मक परीक्षण दिया है। 11 अक्टूबर 2021 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिमनास्ट की तरफ से ये टेस्ट किया गया था, जिसके रिजल्ट सकारात्मक आए है। गौरतलब है कि इस टेस्ट के बाद से दीपा ने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं वर्ष 2018 में उनके घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो लगातार रिकवर ही करती रही है। बता दें कि दीपा कर्माकर में वर्ष 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भारत का नाम रौशन किया था। रियो ओलंपिक में दीपा ने चौथा स्थान हासिल किया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बीएमसी ने 52619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को वर्ष 2023-24 के लिए 52,619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार का बजट अनुमान 2022-23 की राशि (45,949.21 करोड़ रुपये) से 14.52 फीसदी ज्यादा है। यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया, जो स्थानीय निकाय के राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 'वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित इस बजट में 52,619.07 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो 2022-23 के बजटीय अनुमान 45,949.21 करोड़ रुपये से 14.52 प्रतिशत अधिक है।' यह 1985 के बाद पहली बार है, जब देश के सबसे अमीर नगर निकाय के प्रशासन ने किसी प्रशासक के समक्ष बजट पेश किया है, क्योंकि उसके पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल सात मार्च 2022 को समाप्त हो चुका है।

सात ट्रेडिंग सेशन में अदाणी समूह का 9 लाख करोड़ घटा

नई दिल्ली। पिछले सात कारोबारी सेशन में अदाणी समूह का मार्केट कैप नौ लाख करोड़ कम हो गया है। 24 जनवरी 2023 को अदाणी समूह का कुल मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ था तो 3 फरवरी के कारोबारी सेशन के बाद महज 10 लाख करोड़ रह गया। दलाल स्ट्रीट में अदाणी समूह की 10 कंपनियां लिस्टेड हैं ये कंपनियां हैं अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी विल्मार, अदाणी ग्रीन, अदाणी ट्रांसमिशन, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और एनडीटीवी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से इन कंपनियों के शेयर अब तक लगभग 50 प्रतिशत तक लुढ़क चुके हैं। पिछले सात कारोबारी सेशन में अदाणी टोटल गैस के शेयर सबसे ज्यादा पिटे हैं। कंपनी के शेयर 3885.45 रुपये से 51% लुढ़ककर 1901.65 रुपये पर पहुंच गए हैं।

अब सहकारी क्षेत्र से होगी निर्यात क्रांति

नई दिल्ली। आप यदि भारत के विदेश व्यापार के आंकड़ों से वाकिफ हैं तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी। इस समय हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम। इसी वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इससे चालू खाते का घाटा भी बढ़ता है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा। इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा हमारा सहकारी क्षेत्र। इससे अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को फायदा होगा, जिनमें दूर-दराज के गांव भी शामिल हैं। आपको इस बात को जानकारी होगी ही कि साल 2021 में भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया था। इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री हैं अमित शाह। इन्हीं की संकल्पना के बाद एक निर्यात सहकारी समिति के गठन का फैसला हुआ है। इस फैसले को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से भी हरी झंडी मिल चुकी है।

वोडाफोन आइडिया को बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने की मिली इजाजत

नई दिल्ली। सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। उसने वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है। बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी मिलने के बाद सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि संचार मंत्रालय ने 3 फरवरी को एक आदेश पारित किया, कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों को टालने से संबंधित ब्याज और समायोजित सकल राजस्व बकाये को इक्विटी शेयरों में बदले, जिसे भारत सरकार को जारी किया जाएगा। कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सुधार पैकेज के तहत मिली है।

यह मात्र बजट नहीं बल्कि समृद्ध और सशक्त भारत की आधारशिला है

प्रह्लाद सबनानी

केंद्र सरकार का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह दिखा रहा है। यह बजट दरअसल अमृत काल का प्रथम बजट होने के कारण इसे भारत में अमृत काल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट भी कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित अवस्था में ले जाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्र सरकार के पूंजीगत निवेश की राशि में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के 7.50 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जोकि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। इतनी भारी भरकम राशि यदि केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत ढांचे को विकसित करने के लिए खर्च की जा रही है तो इससे देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित होंगे एवं देश में उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि होगी तथा अंतत: निजी क्षेत्र की कम्पनियों को भी अपने पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देश की आर्थिक प्रगति को बल देने के लिए यह एक क्रांतिकारी उपाय कहा जा सकता है।

इसी प्रकार, भारत में आधारभूत संरचना को विकसित स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से रेल बजट के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। इस प्रकार इस मद पर अब नए वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग दुगनी राशि खर्च की जाएगी। रेलवे को विकसित अवस्था में लाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की लागत की कई नई योजनाएं भी प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही, देश में हवाई यातायात को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से 50 अतिरिक्त नए एयरपोर्ट, हेलीपेड, वॉटर

एयरोड्रम आदि बनाए जाएंगे। साथ ही, क्षेत्रीय हवाई संबद्धता को भी और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कुल बजट की राशि का 8 प्रतिशत है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बजट में आवंटित की गई इस राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के कार्य पर किया जाएगा। इससे देश में ही रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे। वैसे, अब तो रक्षा क्षेत्र में उत्पादित उपकरणों एवं हथियारों आदि का भारत निर्यात भी करने लगा है। रक्षा के क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने से देश से इन उत्पादों के निर्यात को भी गति मिलेगी।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित किया जा रहे हैं अत: इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लाई जा रही है। साथ ही, तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर तक के सूक्ष्म उद्योग को करों में छूट दी जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक बल देते हुए 3,400 सरकारी कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने का फैसला किया गया है। इससे देश में नए नए उद्योगों को स्थापित करने में अब और अधिक आसानी होगी।

कृषि का क्षेत्र तो केंद्र सरकार के लिए प्रारम्भ से ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और किसानों की आय को दुगना किए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आज भी देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है एवं अपनी आजीविका के लिए मुख्यत: कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। अत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी पालन और मत्यस्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए की योजना है। मत्स्य उपयोजना में 6,000 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।

समाज को जोड़ने का काम करती रही हैं यात्राएं

राजेश बादल

भारत की आजादी के बाद सबसे लंबी और सकारात्मक यात्रा हाल ही में श्रीनगर में समाप्त हो गई। इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत को जोड़ना बताया गया था लेकिन एक वर्ग इसके पीछे सियासी गंध खोजता रहा है। इसके संपन्न होने के बाद अब यह देश चर्चा कर सकता है कि यात्रा का उद्देश्य असल में सियासी था अथवा वाकई यह सामाजिक सद्भाव और सारे हिंदुस्तान को एकजुट करने वाला था?

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा के बाद इस प्रश्न पर बहस स्वाभाविक है। विविधताओं से भरे इस देश में कुछ समय से सामाजिक ताने-बाने को झटके लगने के समर्थन में तर्क दिए जाते रहे हैं। यह भी गंभीरता से कहा जाता रहा है कि सियासत की अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी यक्ष प्रश्न है कि क्या वास्तव में डेढ़ सौ करोड़ की आबादी का यह राष्ट्र इन दिनों धर्मों, जातियों, उपजातियों, भाषा और रीति-रिवाजों के आधार पर सदियों से चली आ रही अनेकता में एकता की राह से भटक रहा है? इन सारे सवालों के उत्तर आज के भारत में खोजने की जरूरत है। सबसे पहले विचार इस पर होना चाहिए कि क्या आज का भारत असल में वैसा ही है, जैसा महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नायकों ने बनाना चाहा था। आजादी के लिए हुई लड़ाई में कमोबेश सभी धर्मों के मानने वालों ने कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया था। उन्होंने एक ऐसे स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहा था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त हो।

इसी कारण संविधान में भी इस भावना का सम्मान किया गया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पचहत्तर साल में धीरे-धीरे हमने लोकतंत्र में नव सामंतवाद को जड़ें जमाते देखा है और सामंती मानसिकता कभी भी अवाम के हक में काम नहीं करती। इस कारण आम नागरिक के हित और अधिकार हाशिए पर जा रहे हैं। आज भी समूचे संसार में भारत की जितनी प्रतिष्ठा है, वह यहां सभी मजहबों को बराबर सम्मान और सारी विचारधाराओं को संरक्षण देने के कारण है। किसी एक संस्कृति, किसी एक समाज को दूसरे से कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही कोई समुदाय अन्य समुदाय के लिए खतरा बना।

अलबत्ता अस्थायी तौर पर रिश्तों में ज्वार-भाटे आते रहे, जो हिंदुस्तान जैसे विराट और प्राचीन देश में एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर देश का हालिया दौर एक बेहद नाजुक पड़ाव से गुजर रहा है। इस पड़ाव पर हम पाते हैं कि सदियों से साथ रहते आए लोग एक-दूसरे को काटने के लिए दौड़ने लगे हैं। यह अजीब सा मंजर है, जिसमें गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक तरफ हम वसुधैव कुटुम्बकं की बात करते हैं तो दूसरी ओर मजहब के आधार पर अपने-अपने खोल में बंद होते जा रहे हैं। एक तरफ सारा विश्व भारतीय नौजवानों और उनकी प्रतिभा को सलाम कर रहा है तो दूसरी तरफ उस नई नस्ल को मानसिक रूप से प्रदूषित करने के प्रयास भी होते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र की विकास धारा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे माहौल में किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी।

मोदी से मुकाबले के लिए तैयार राहुल

ललित गर्ग

श्रीनगर के लाल चौक पर कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य समापन निश्चित ही कांग्रेस को नवजीवन देने का माध्यम बना है, इससे राहुल गांधी की छवि एकदम नये अन्दाज में उभर कर सामने आयी है और एक सकारात्मक राजनीति की पहल हुई है। वैसे भी भारत की माटी में पदयात्राओं का अनूठा इतिहास रहा है। असत्य पर सत्य की विजय हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा की हुई लंका की ऐतिहासिक यात्रा हो अथवा एक मुट्ठी भर नमक से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिला देने वाला 1930 का डाण्डी कूच, बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा हो अथवा राष्ट्रीय अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव और अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व भाव से समर्पित एकता यात्रा, यात्रा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जीवन में पैदल यात्रा को जन-सम्पर्क का सशक्त माध्यम स्वीकारा गया है। ये पैदल यात्राएं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करती हैं। लोक चेतना को उद्बुद्ध कर उसे युगानुकूल मोड़ देती हैं। भगवान् महावीर ने अपने जीवनकाल में अनेक प्रदेशों में विहार कर वहां के जनमानस में अध्यात्म के बीज बोये थे। जैन मुनियों की पदयात्राओं का लम्बा इतिहास है। वर्ष में प्राय: आठ महीने वे पदयात्रा करते हैं, जैन आचार्य श्री महाश्रमण ने भी तीन पड़ोसी देशों सहित सम्पूर्ण भारत की अहिंसा यात्रा की। इन यात्राओं की श्रृंखला में राजनीति उद्देश्यों के लिये राहुल गांधी की यात्रा ने नये स्तस्तिक उकेरे हैं। भले ही अनेक मोर्चों पर राहुल की यह यात्रा विवादास्पद बनी, आलोचनाओं की शिकार हुई। लेकिन इस सब स्थितियों के बावजूद राहुल गांधी ने राजनीतिक पटल पर वो कारनामा कर ही दिखाया जिसकी उम्मीद उनके विपक्षी तो दूर की बात, अपने भी नहीं करते थे।

इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने एक इतिहास गढ़ा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 147 दिन की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर राहुल अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ अपनों को भी एक संदेश देने में कामयाब रहे हैं। संदेश यह कि धीरे-धीरे ही सही उन्होंने अपनी अपरिपक्व राजनेता की छवि में बदलाव लाने का प्रयास किया है। यह बदलाव उन्हें गंभीर, अनुभवी एवं राजनीतिक कौशल में दक्ष नेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस पर यात्रा के समापन पर कुछ बड़ी अटपटी एवं राजनीतिक बातें कहकर नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद जम्मू-कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था को लेकर जो प्रश्न उठाए, वे इसलिए हास्यास्पद लगे कि स्थितियां अच्छी नहीं होतीं तो क्या वे वहां पर तिंरगा फहरा सकते थे? सुरक्षा एवं व्यवस्था के हालात अच्छे बने हैं तभी उनकी यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो पायी। इसके लिये उन्हें सरकार का आभार जताना चाहिए न कि आलोचना की जाये। उन्होंने अपनी इस यात्रा को न तो अपने लिए बताया और न ही कांग्रेस पार्टी के लिए। बल्कि कहा कि यह यात्रा देश के लिए थी। राजनेताओं द्वारा देश एवं देश की जनता के नाम पर ऐसे प्रपंच होते रहे हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस की लगातार निस्तेज होती छवि एवं स्थिति में प्राण फूंकने, उम्मीद जगाने एवं जोश भरने के लिये एक ऐसी यात्रा या ऐसे बड़े उपक्रम की जरूरत थी, उस उद्देश्य को पूरा करने एवं लक्ष्य हासिल करने में यात्रा सफल रही है। जिसने भी इस तरह की यात्रा की सलाह दी, वह अवश्य ही राजनीति का अनुभवी व्यक्ति रहा है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक फैसला लेने के बाद ऐसे अनेक कदम उठाए गए, जिनसे आतंकियों और अलगाववादियों के दुस्साहस का दमन हुआ। घाटी में शांति एवं अमन कायम करने में भाजपा के प्रयत्नों की सराहना भले ही वे राजनीतिक कारणों से न कर पायें, लेकिन ऐसे अवसर पर सुरक्षा एवं व्यवस्था जैसे प्रश्नों को उठाना उचित नहीं था। घाटी के बदले हुए वातावरण के कारण ही कांग्रेस कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कर सकी। यदि हालात बेहतर नहीं होते तो संभवत: वहां भारत जोड़ो यात्रा प्रतीकात्मक रूप से ही हो पाती। शहरों, देहातों, खेड़ों और ग्रामीण अंचलों में जाकर सामूहिक एवं व्यक्तिगत जनसम्पर्क करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्र-निर्माण में योगदान के इतिहास को जीवंत किया है। उन्होंने अनेक प्रभावी प्रतीकों एवं बयानों से नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा सरकार पर हमले भी किये हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को आज एक करिश्माई नेता की जरूरत है, जो मोदी जैसे सशक्त नेता एवं भाजपा जैसी सुदृढ़ पार्टी का मुकाबला कर सके। स्वयं को देश का नेतृत्व करने में सक्षम साबित कर सके। राहुल गांधी की पप्पू छवि के कारण ऐसा दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब राहुल भले ही पूरी तरह नहीं, पर आंशिक रूप में मोदी को चुनौती देने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। इसे लोकतंत्र के लिये एक शुभ घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। राहुल की इस यात्रा से पार्टी को कितना और खुद राहुल को कितना फायदा होगा यह भविष्य ही बताएगा। श्रीनगर एवं देश के अन्य हिस्सों में भी इस यात्रा के माध्यम से विपक्षी दलों की एकता के व्यापक प्रयत्न हुए, लेकिन उनमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। श्रीनगर में भी मौसम की खराबी के कारण विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच सका।

भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यह प्रभावी तरीके से उद्घाटित हुआ कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। पार्टी के भीतर उफने विद्रोह की लौ को शांत करने के लिये भी यह यात्रा निकाली गयी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अपनी नयी छवि एवं ऊर्जाशील बने राहुल अब विपक्षी एकता को लेकर क्या कदम उठाते हैं, पार्टी के भीतरी कलह को कितना शांत कर पाते है, भाजपा को भी ऐसी यात्रा निकालने जैसी कितनी चुनौतियां वे दे पाते हैं, भाजपा के विरोध में खड़े दल क्या राहुल के नेतृत्व में एकजुट हो पायेंगे, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा। राहुल को अपने विरोधाभासी बयानों से बचना होगा। अभी तक वे बहुत सशक्त रूप में यात्रा का उद्देश्य भी नहीं बता पाये हैं। कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के वातावरण को दूर करने के लिए की गई, लेकिन जब यह यात्रा दिल्ली आई तो स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने करीब 2800 किलोमीटर की अपनी यात्रा में कहीं पर भी नफरत नहीं देखी। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि देश में नफरत फैलने का निराधार शोर मचाया जा रहा था? घाटी में अशांति एवं अव्यवस्था का राग अलापा जा रहा है। इस तरह अनेक मोर्चों पर राहुल गांधी खुद ही भाजपा की उपलब्धियों के कसीदे काढ़ते दिखे। चाहे देश में नफरत का न होना हो या कश्मीर में शांति व्यवस्था का बने होना हो।

निस्संदेह, हर पदयात्रा के राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत ऐसे वक्त में की थी जब देश को आजादी के लिये जोड़ने एवं कांग्रेस में स्फूर्ति लाने की महती आवश्यकता थी। वहीं चंद्रशेखर भी पार्टी के आंतरिक राजनीतिक हालात से क्षुब्ध थे। लालकृष्ण आडवाणी ने हिन्दुत्व को मजबूती देने के लिये यात्रा की। उन यात्राओं ने देश का मिजाज बदलने में अपना योगदान दिया था और आज भी उन यात्राओं को याद किया जाता है। क्या राहुल गांधी की यात्रा को भी याद किया जाएगा? क्या कमोबेश कांग्रेस पार्टी अपने संक्रमणकाल से उभर पायेगी? नेतृत्व के प्रश्न पर भी कोई उजाला होगा? क्या लगातार निस्तेज होती पार्टी में प्राण-संचार हो पायेगा? इन जटिल से जटिलतर स्थितियों से उबरने में इस यात्रा ने अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन उसका असर एवं प्रभाव देखना बाकी है। एक बड़ा लक्ष्य कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का भी है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस यात्रा के माध्यम से देश की जनता को आकर्षित करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई विमर्श खड़ा करने की भूमिका तैयार हुई है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक परियोजना थी, इससे एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता को सुनिश्चित किया गया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

इन (प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय) तीनों कोशों का समुच्चय ही लिङ्ग शरीर है। जिसमें अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है, वह आनन्दमय कोश है। इसे ही कारण शरीर कहते हैं।

इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, प्राणादि पञ्चक, वियदादिपञ्चक (पाँच महाभूत), अन्त:करण चतुष्टय, काम, कर्म और अविद्या ये पुर्यष्टक (आठ पुरियों का समूह) कहलाता है।

ईश्वर की आज्ञा से विराट् ने व्यष्टि में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विश्वत्व को प्राप्त किया अर्थात् विश्व की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मा, चिदाभास, विश्व, व्यावहारिक, जाग्रत, स्थूल देहाभिमानी और कर्मभू ये विश्व के विभिन्न नाम हैं।

ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा, व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तैजसत्व को प्राप्त हुआ। तैजस, प्रातिभासिक और स्वकल्पित ये तैजस के नाम हैं।

ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त, व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञत्व को प्राप्त हुआ। प्राज्ञ, अविच्छिन्न, पारमार्थिक और सुषुप्ति-अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम हैं।

पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है। वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परन्तु व्यावहारिक और प्रातिभासिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते।

अन्त:करण में जो चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है, वही अवस्थात्रय (जागत्, स्वप्न और सुषुप्ति) का भागी होता है। चैतन्य तत्त्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटीयन्त्र के समान उद्विग्न (चंचल) होता है, जो निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता है।

इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं। जाग्रत् अवस्था उसे कहते हैं, जिसमें श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने देवता के अनुग्रह (शक्ति) से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। इस अवस्था में जीव भ्रूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यन्त व्याप्त रहता है और कृषि से श्रवण तक (अर्थात् अपनी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के) समस्त कार्यों को सम्पादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकान्तर (परलोक) में भी है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थककर विश्रान्ति पाने हेतु अन्दर के विश्राम स्थल में 193 इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है। इन्द्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर, जाग्रत् अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य-ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत् स्फुरणा होती है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। उस अवस्था में विश्व (स्थूल शरीर भी व्यष्टि- चेतना शक्ति) जाग्रत् अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तैजसत्व को प्राप्त करता है। तत्पश्चात् अपनी वासना के अनुरूप अपने ही भासा (तेज) के द्वारा एक विचित्र जगत् की सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छानुसार उसका भोग करता है।

चित्त की एकीकरण (एकाग्रता से युक्त) अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से थककर पक्षी पंखों को समेट कर अपने नीड़ (घोंसले) की ओर गमन करता है, उसी प्रकार जीव भी जाग्रत् और स्वप्रावस्था के प्रपञ्चों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनन्द भोगता है।

क्रमश:

सामाजिक समरसता के प्रेरक रहे संत रविदास

मृत्युंजय दीक्षित

महान संत रविदास का जन्म धर्मनगरी काशी के निकट मंडुआडीह में संवत 1433 में हुआ था। उन्होनें अपनी वाणी के माध्यम से आध्यात्मिक, बौद्धिक व सामाजिक क्रांति का सफल नेतृत्व किया। उनकी वाणी में निर्गुण तत्व का मौलिक व प्रभावशाली निरूपण मिलता है। कहा जाता है कि भक्त रविदास का उद्धार करने के लिये भगवान स्वयं साधु वेष में उनकी झोपड़ी में आये थे लेकिन रविदास ने उनके द्वारा दिये गये पारस पत्थर को स्वीकार नहीं किया।

मुस्लिम शासकों का प्रयास था कि येन केन प्रकारेण हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाये। इसी के चलते सदना पीर नाम का एक मुस्लिम विद्वान रविदास को मुस्लिम बनाने के लिये उनसे मिलने पहुंचा। सदना पीर ने शास्त्रार्थ करके हिंदू धर्म की निंदा की और इस्लाम की प्रशंसा की। संत रविदास ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर इस्लाम के दोष बता दिये। संत रविदास के तर्कों के आगे सदना पीर टिक न सका। सदना पीर आया तो था संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिये लेकिन वह स्वयं हिंदू बन बैठा।

उस काल में युग प्रवर्तक स्वामी रामानंद काशी में पंच गंगाघाट में रहते थे। रविदास ने उन्हीं को अपना गुरू बना लिया। स्वामी रामानंद ने उन्हें रामभजन की आज्ञा दी व गुरूमंत्र दिया रं रामाय नम:। गुरूजी के सान्निध्य में ही उन्होनें योग साधना और ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्होनें वेद, पुराण आदि का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया।

कहा जाता है कि भक्त रविदास का उद्धार करने के लिये भगवान स्वयं साधु वेष में उनकी झोपड़ी में आये थे लेकिन रविदास ने उनके द्वारा दिये गये पारस पत्थर को स्वीकार नहीं किया।

संत रविदास ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारी चोट की। संत रविदास का कहना था कि हमें सभी में समान प्राण-तत्व का अनुभव करना चाहिये। भारतीय संतों ने सदा अहिंसा वृति का ही पोषण किया है। संत रविदास जाति से चर्मकार थे। लेकिन उन्होनें कभी भी जन्मजाति के कारण अपने आप को हीन नहीं माना।

उन्होनें परमार्थ साधना के लिये सत्संगति का महत्व भी स्वीकारा है। वे सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संत के आगमन से घर पवित्र हो जाता है। उन्होनें श्रम व कार्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा कहा कि अपने जीविका कर्म के प्रति हीनता का भाव मन में नहीं लाना चाहिये। उनके अनुसार श्रम ईश्वर के समान ही पूजनीय है। संत रविदास के प्रभु किसी भी प्रकार की सीमाओं से नहीं बंधे हैं वे तो घट-घट व्यापी हैं। उनका मत है कि प्रभु ही सबके स्वामी हैं। वे उच्चकोटि के आध्यात्मिक संत थे। उन्होनें अपनी वाणी से आध्यात्मिक व बौद्धिक क्रांति के साथ- साथ सामाजिक क्रांति का भी आहवान किया। वे प्रभु राम को ही परम ज्योति के रूप में स्वीकारते थे तथा निर्गुण तत्व का मौलिक निरूपण करते थे। संत रविदास कवि होने के साथ-साथ एक क्रांतिकारी व मौलिक विचारक भी थे। उन्होनें परमात्मा से संपर्क जोड़ने के लिये नामस्मरण, आत्मसमर्पण व दीनभावना का सहारा लिया तथा अपने पदों में समाज के दीनहीन वर्ग के उत्थान की कामना की। उनकी भक्ति का रूझान इतना बढ़ा कि वे प्रभु का मानसी पूजन करने लगे व प्रभु से प्राप्त पारसमणि को भी अस्वीकार कर दिया। संत रविदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत भ्रमण किया तथा दीन हीन दलित समाज को उत्थान की नयी दिशा दी।

वे सामाजिक समरसता के प्रतीक महान संत थे। चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनीं वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गये। समाज में सभी स्तर पर उन्हें सम्मान मिला। वे महान संत कबीर के गुरूभाई तथा भक्त मीराबाई के गुरू थे। श्री गुरुग्रंथ साहिब में भी उनके पदों का समायोजन किया गया है। वर्तमान सामाजिक वातावरण में समरसता का संदेश देने के लिये संत रविदास का जीवन आज भी प्रेरक है।

विकास मजबूरी, संतुलन जरूरी

अनुज अग्रवाल

कुछ न होने वाला, डराओ मत, हमेशा नकारात्मक ही क्यों सोचते व बोलते हो, प्रकृति के पास अपार संसाधन हैं इसलिए उनके उपयोग पर रोक टोक न लगाओ आदि आदि। प्रकृति प्रेमी और पर्यावरणविद् अधिकांश इसी तरह के जुमले सुनने के आदि होते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और हादसे होते हैं तब कुछ समय के लिए उनकी बातो पर चर्चा होती है किंतु शीघ्र ही विकासवादी उतावलेपन का शिकार हो जाते हैं और संतुलन खो, अनियंत्रित विकास और आपाधापी का शिकार हो जाते हैं। भौतिक जीवन के सुख पाने के लिए आवश्यक संसाधनों की होड़ के बीच आम आदमी तो उतावला हो ही जाता है । उसके इन उतावलेपन व ललक को नेता, नौकरशाह व कारपोरेट घराने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अनियंत्रित व अनियोजित विकास का अंबार खड़ा कर देते हैं। बिना योजना व संवेदनशीलता से भरा यह नींव हीन विकास शेने शेने बिखरने लगता है और अंतत: जोशीमठ के दरकने के रूप में सामने आता है।बस तबाही ही तबाही। बाज़ार और पूंजीवाद के अति स्वार्थ व अबाध लाभ के लालच ने व्यक्ति के जीवन से संतुलन व सहजता को समाप्त कर दिया है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक संसाधन एक सामान्य आवश्यकता होते हैं किंतु हौड़ व दौड़ में हम जीवन की शांति को प्राथमिकता देना भूल गए हैं और संसाधनों की होड़ में पड़ गए हैं। इसी का परिणाम पूरे देश में अनियंत्रित विकास के रूप में सामने आता गया है। हमारे शहर अराजकता का नमूना हैं। बिना पर्याप्त जल प्रबंधन, जल निकासी,सीवर, कूड़ा संग्रहण , निस्तारण व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भयावह प्रदूषण युक्त बेतरतीब शहर भारत में आम हैं। टाउन प्लानिंग से इनका कोई वास्ता ही नहीं। क्षमता से कई गुना आबादी व हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी का शिकार। कोई भी बिल्डिंग व मकान ऐसा नहीं जिसमे नियमों के अनुसार निर्माण हुआ हो, हर ओर अतिक्रमण व अवैध क़ब्ज़े। हर नियम , कायदे व कानून की धज्जियाँ उड़ाते लोग व उड़वाता तंत्र। ऐसी स्थिति में देश का हर शहर, कस्बा व गांव जोशीमठ जैसी स्थिति का शिकार होना ही है। निश्चित रूप से सभी को अच्छी जीवन शैली व न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु संसाधन चाहिए पर इनको संयमित,योजनाबद्ध व विकेंद्रित करना अनिवार्य है। अन्यथा बस यह दस , बीस या तीस वर्षों की बात ही रह गई है जब जोशीमठ जैसे समाचार देश के हर भाग से हर रोज आया करेंगे वास्तव में आने भी लगे हैं। हमारी अनियंत्रित जीवन शैली व सोच ने हमे ही एक अंधे कुएं में धकेल दिया है और जिस धरती पर हमने अनंत समय तक खुशहाल जीवन जीने की कल्पना की थी वह चंद दशकों में ही सिमट जाती दिख रही है। पेट्रोलियम पदार्थों, कोयले, मांसाहार व रसायनों के अंधाधुंध उपभोग ने इस धरती के पर्यावरण संतुलन को छिन्न भिन्न कर दिया है।इस कारण धरती का बढ़ता तापमान सब कुछ निगलने पर उतारू है। हज़ारो वर्षों से प्रकृति व हमारा शरीर जिस तापमान को झेलने का आदि हो चुका है अब वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यह बढ़ती तपन धीरे धीरे सब कुछ झुलसा देगी। अगर जंगल,खेती व पेड़ सूख व सिमट गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। पर्यावरणविद् कह रहे हैं कि बस अगले कुछ वर्षों में ही हम सामान्य जीवन जीने लायक नहीं रहेंगे और अगले कुछ दशकों में बड़ी मात्रा में सिमट जाएँगे। यह बहुत गंभीर व चिंतनीय स्थिति है। हम मानव, जीव जंतुओं व पशु पक्षियों को नित नई बीमारियों, महामारियों,कुपोषण, खाद्य व जल संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाढ़, सूखा, लू, जंगलों में आग , भूकंप, चक्रवात, तूफ़ान आदि अब कई गुना होते जाएंगे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद कर देंगे। समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटो को निगलता जाएगा। हमे बड़ी मात्रा में लोगों के पलायन के लिए तैयार रहना होगा। ये सब बड़ी मात्रा में गृहयुद्ध, बड़े युद्ध, मंदी, महंगाई व बेरोजगारी को बढ़ाते जाएँगे।हम बड़ी मात्रा में संसाधनों की कमी से दो चार होते जाएँगे। संसाधनों के लिए संघर्ष व युद्ध मानव का इतिहास रहे हैं। इसीलिए रूस- यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की संभावनाएं बहुत हैं। युद्ध व हथियारों की जिस होड़ में दुनिया पड़ गई है वो आत्मघाती हो चली है। ऐसे में सभ्यताओं का सिमटना तय है। विकास व बाज़ार एक अच्छे जीवन की अनिवार्य शर्त है किंतु यह अनियंत्रित न हो , ऐसा ध्यान सभी को रखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन व आईटी ने जीवन को सरल व सुगम तो बनाया है किंतु अब ये रोजगार निगलती जा रही है। यह स्थिति देश व दुनिया को एक ख़तरनाक मोड़ की ओर धकेल रही है। यह अनिवार्य होना चाहिए की सरकार, राजनीतिक दल व सामाजिक संस्थान जनता में पर्यावरण अनुकूल विकास, संयमित, संस्कारित व न्यूनतम संसाधनों वाली जीवन शैली की योजनाओं को लेकर शिक्षा दें व उसको चुनावी मुद्दा व नीतियों का आधार बनाए और धर्म , जाति, भाषा व क्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए। अन्यथा अपेक्षित नुक़सान कई गुना हो सकता है और मानव जाती अस्तित्व के संकट का सामना भी कर सकती है। बाजार, लूट व शोषण से परे जीडीपी के चंगुल से मुक्त योजनाबद्ध विकास जिसमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो व पर्यावरणविदो की सहमति हो , जनसंख्या नियंत्रण,हरित ऊर्जा, जैविक व प्राकृतिक कृषि, नये तापमान में अनुरूप नई कृषि पद्धतियों की खोज , बढ़ते तापमान के साथ जीवन व सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुकूलन व तापमान वृद्धि को रोकने के हर संभव द्रुतगामी प्रयास हम सभी को युद्ध स्तर पर करने होंगे।

गांधी आज

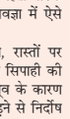

सविनय अवज्ञा (भाग -01)

सविनय अवज्ञा दो तरह की हो सकती है—किसी विशेष अन्यायकारी हुक्म या कानून की, केवल उसी हुक्म या कानून को रद्द कराने भर के लिए और असहयोग के ही खास कदम की भांति, अन्याय-अधर्म किए अथवा निर्दोष या तटस्थ जनता को अनुचित असुविधा पहुँचाए बिना तोड़े जा सकनेवाले, आमतौर से तमाम कानूनों की है।

मनुष्य चोरी से किसी कानून के डर से ही दूर नहीं रहता बल्कि उसे अधर्म समझ कर ही बचता है। अत: सविनय अवज्ञा में ऐसे कानून नहीं तोड़े जा सकते।

गाड़ी को सड़क के गलत बाजू से न चलाना, रास्तों पर आवागमन का नियमन करने के लिए तैनात पुलिस के सिपाही की आज्ञा मानना, रात को देरतक शोरगुल न मचाना, महत्त्व के कारण बिना रेल की जंजीर न खींचना, इत्यादि हुक्मों को तोड़ने से निर्दोष तथा तटस्थ मनुष्यों को अनुचित असुविधा होती है, इसलिए ऐसी आज्ञाओं को भी भंग नहीं किया जा सकता।

किन्तु मनुष्य के राज्य के प्रति असंतोष न दिखाने हो सकते हैं-राज्य से उसे संतोष हो और इस कारण उसके प्रति उसकी भक्ति हो, अथवा कानून से डरकर । सत्याग्रही कानून से डरकर सरकार के प्रति असंतोष प्रदर्शित करने से न रुकेगा, और कहीं सविनय अवज्ञा की आवश्यकता उपस्थित होने पर तो ऐसे कानून का तोड़ना फर्ज भी हो सकता है। दो कारण

उसी प्रकार उचित सीमा के अंदर रहकर, अपने देश के किसी भी हिस्से में जाना और रहना तथा शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, सभा सम्मेलन, जन-सेवा के कार्य, अनुचित कार्यों अथवा बुराईयों के खिलाफ पिकेटिंग आदि करना या इनका आयोजन जनता का साधारण अधिकार है; इस हक पर सरकार की ओर से प्रतिबंध हो तो सत्याग्रही उस आज्ञा को निम्नलिखित कारणों से मानता है।

क्रमश:...

संक्षिप्त समाचार

राज्य स्तरीय सरस मेला 13 से 23 फरवरी तक

बिलासपुर। फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सरस मेले की तैयारियों का आज जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जयश्री जैन और सहायक कलेक्टर श्री वासु जैन ने जायजा लिया। राज्य स्तरीय सरस मेले का आयोजन व्यापार विहार में किया जाएगा। यह सरस मेला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में लगाया जा रहा है। श्रीमती जैन ने इस दौरान अधिकारियों को तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी को सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा जवाबदारी से करने कहा है। गौरतलब है कि सरस मेले में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्य की स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इस मेले में लोगों को महिला शिल्पकारों के हुनर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक दो घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस मेले में मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहां अलग-अलग राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानने एवं समझने का मौका मिलेगा।

कांग्रेस को सता रहा अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन का डर

रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री, नगरी प्रशासन मंत्री, रायपुर कलेक्टर महापौर आयुक्त और स्मार्ट सिटी रायपुर के एमडी को धरना स्थल को स्मार्ट धरना स्थल बनाने हेतु पत्र लिखा था। किंतु पूरे 11 दिन बाद बूढ़ा तालाब धरना स्थल को बदल कर नया रायपुर परिवर्तित कर दिया गया है। यह इस बात का घोतक है कि अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन से सरकार घबरा गई है। सत्ता का डर उनको सता रहा है जन घोषणा पत्र में कर्मचारियों को किए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और बिना वादा पूरा किए चुनावी वर्ष को निकाल पाना मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए डर से धरना स्थल बूढ़ा तालाब रायपुर को बदल कर तूता नवा रायपुर कर दिए।

छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने किया साइक्लिस्ट इंद्रसेन अग्रवाल का सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज का 47वा वार्षिक अधिवेशन पिछले दिनो इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि करने वाले सदस्यों का सम्मान किया गया। इस मौके पर साइक्लिस्ट इंद्रसेन अग्रवाल का भी सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि इंद्रसेन अग्रवाल जो कि शहर के साइकिलिस्ट है, जिन्होंने एक ही सत्र में 200,300,400 एवम 600 किमी साइकिल चलाकर सुपर रेंडोनियर्स का खिताब अपने नाम कर अग्रवाल समाज के प्रथम सुपर रेंडोनियर बन चुके है। साथ ही इंद्रसेन अग्रवाल पिछले वर्ष मनाली से खारदुंगला जो की विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में साइकिल चलाकर एक नया मुकाम तय किया था। वर्तमान में इन्होंने नर्मदा परिक्रमा जोकि अमरकंटक से गुजरात तक जाकर, एवम वापस अमरकंटक आकर साइकिल से परिक्रमा संपन्न की। उनकी यह यात्रा 34 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर चलाकर संपन्न हुई।

सरयूपारीण ब्राम्हण सभा का कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

रायपुर। स्वाथ्य ही असल धन है की अवधारणा को लेकर आगामी 5 फरवरी दिन रविवार को विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सको के सहयोग से सरयूपारीण ब्राम्हण सभा के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रस्तावित है। शिविर में एलोपैथी, आर्युवेदिक ,होम्योपैथी के विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर सरयूपारीण ब्राम्हण सभा भवन रिंग रोड संजय नगर के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2बजे तक आयोजित होगा। पूर्णतः निःशुल्क शिविर होगा,आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण भी किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न रोगों की जांच में लगने वाली राशि मे भी सम्बंधित चिकित्सा केंद्र से छूट हेतु सुविधा भी तय की जायेगी।

संत रविदास जयंती पर प्रदेश में लगेंगे आयुष मेले

भोपाल। आयुष विभाग संत रविदास जयंती 5 फरवरी को प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में आयुष मेले आयोजित कर रहा है। आयुष मेले के आयोजन के संबंध में विभाग ने आयुष जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। आयुष मेले में संत रविदास जी के उपदेशों का भी स्मरण किया जाएगा और जन-सामान्य को इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आयुष मेले में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पैथी के माध्यम से रोगियों का इलाज किया जायेगा। शिविर में निःशुल्क दवाई वितरण की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही शिविर में योगाभ्यास एवं योग से लाभ की जानकारी जन-सामान्य को दी जाएगी। शिविर में गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शिविर में स्त्री रोग, शिशु रोग उपचार के साथ ही रोगियों के ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच की भी व्यवस्था की जाए।

मोबाईल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

■ मिलेंगे रागी, कोदो, कुटकी से बने लजीज व्यंजन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश के पहले मोबाईल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर रागी से बना केक काटा। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे मिलेट के उपभोग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने इस मोबाइल कैफे का संचालन करने वाली महिला समूह को अपनी शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन रायगढ़ की पहल पर शुरू हुआ यह मिलेट ऑन व्हील्स कैफे एक चलता फिरता मिलेट कैफे होगा। जिसमें रागी, कोदो, कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जायेंगे। इसे अनुभव महिला समूह संचालित करेगा। इस मोबाइल मिलेट कैफे में रागी का चीला, डोसा, मिलेट्स पराठा, इडली, मिलेट्स मंचूरियन, पिज्जा, कोदो की बिरयानी और कुकीज जैसे पकवान चखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर मिलेट मिशन चलाया जा रहा है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का ना सिर्फ समर्थन मूल्य घोषित किया गया अपितु समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है। इस पहल से छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का रकबा डेढ़ गुना बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों और मीडिया के लिए मिलेट्स से बने व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए दोपहर भोज का भी आयोजन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में मिलेट कैफे भी प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नथिया-नवागांव में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं।

सौन्दर्यीकरण व जीर्णोधार कार्य का संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने किया भूमि पूजन

रायपुर। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय शनिवार को टाटीबंध रिंग रोड नंबर 02 स्थित शमशान घाट का भूमि पूजन किया, जिसके अंतर्गत शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोधार किया जायेगा। विकास उपाध्याय ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के आग्रह पर इस शमशान घाट का जीर्णोधार किया जा रहा है जिसमें नाला निर्माण, सडक निर्माण, गार्डनिंग, बैठने के लिये समुचित व्यवस्था जिसमें सेड, चेयर एवं वाहन खडा करने के लिये पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। वर्तमान में इस शमशान घाट की स्थिति ठीक न होने के कारण दाह संस्कार के लिये दूर जा रहे थे, अब आसपास के लोगों को दाह संस्कार के लिये दूर नहीं जाना पडेगा। उपाध्याय द्वारा लगातार पश्चिम विधानसभा में जनहित के कार्य किये जा रहे है एवं जनता के द्वारा मांग किये जाने पर ही कार्यो को प्रगति दी जा रही है.उपाध्याय ने कहा रायपुर पश्चिम विधानसभा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है पिछले कई सालों से जिन कार्यो को करने की मांग आ रही थी उनको पूर्व के जनप्रतिनिधियो द्वारा नजर अंदाज किया जाता रहा था उन्ही कार्यो को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करना मैने अपना कर्तव्य समझा और लगातार वही सब कार्य पूर्ण किये गये और बचे कार्य पूर्ण किये जा रहे है।

आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का त्रिवेणी संगम राजिम माघी पुन्नी मेला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित पवित्र धार्मिक नगरी राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है। राजिम में तीन नदियों का संगम है इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, यहाँ मुख्य रूप से तीन नदियां बहती हैं, जिनके नाम क्रमशः महानदी, पैरी नदी तथा सोंढूर है।संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव जी विराजमान है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से राजिम मेले को राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था, वर्ष 2005 से इसे कुम्भ के रूप में मनाया जाता रहा था, और अब 2019 से राजिम माघी पुन्नी मेला के रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग एवं स्थानीय आयोजन समिति के तत्वाधान में होता है। मेला की शुरुआत कल्पवास से होती है। पखवाड़े भर पहले से श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालु पटेश्वर, फिंगेश्वर, ब्रम्हनेश्वर, कोपेश्वर तथा चम्पेश्वर नाथ के पैदल भ्रमण कर दर्शन करते हैं तथा धुनी रमाते हैं। 101 कि?मी? की यात्रा का समापन होता है और माघ पूर्णिमा से मेला का आगाज होता है।

इस वर्ष 5 फरवरी माघ पूर्णिमा से 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि तक राजिम माघी पुन्नी मेला आयोजित किया गया है। राजिम माघी पुन्नी मेला में विभिन्न जगहों से हजारों साधू संतों का आगमन होता है, प्रतिवर्ष हजारो की संख्या में नागा साधू, संत आदि आते हैं, तथा विशेष पर्व स्नान तथा संत समागम में भाग लेते हैं, प्रतिवर्ष होने वाले इस माघी पुन्नी मेला में विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान श्री राजीव लोचन तथा श्री कुलेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं और अपना जीवन धन्य मानते हैं। लोगो में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथपुरी जी की यात्रा तब तक पूरी नही मानी जाती, जब तक भगवान श्री राजीव लोचन तथा श्री कुलेश्वर नाथ के दर्शन नहीं कर लिए जाते, राजिम माघी पुन्नी मेला का अंचल में अपना एक विशेष महत्व है। राजिम अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला एक छोटा सा शहर है। राजिम गरियाबंद जिले का एक तहसील है। प्राचीन समय से राजिम अपने पुरातत्वों और प्राचीन सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। राजिम मुख्य रूप से भगवान श्री राजीव लोचन जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। राजिम का यह मंदिर आठवीं शताब्दी का है। यहाँ कुलेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है। जो संगम स्थल पर विराजमान है। राजिम माघी पुन्नी मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा विविध सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन होते हैं।

पाऊवारा स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ

दुर्ग। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाऊवारा के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें प्रायमरी, पूर्व माध्यमिक व हायर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां गई उत्कृष्ट गतिविधियों के विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार कि शिक्षा भी स्कूल के माध्यम से मिलनी चाहिए विशेष अतिथि जनपद अध्यक्ष देवेन्द्र देशमुख ,कृषि सभापति योगिता चन्द्राकार ,जनपद उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़ , सभापति राकेश हिरवानी राजेश साहू अध्यक्ष सहकारी समिति बोरीगारका, दीपक साहू उपसरपंच, वेदनारायण साहू, गज्जु हिरवानी, प्रदीप साहू इब्राहिम खान, उपस्थिति थे कार्यक्रम में प्राचार्य सुनील यादव, प्रधान पाठक सहित स्कूल के स्टाप व छात्र छात्रा उपस्थित थे।

प्रदेश में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को रियायती बिजली का लाभ

रायपुर। बिजली उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ राज्य में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को रियायती बिजली का लाभ मिल रहा है। इन परिवारों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लागू की गई हाँफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित 41.94 घरेलू बिजली उपभोक्ता, 16.82 लाख बी.पी.एल बिजली उपभोक्ता, 6.26 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं। हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह की गई 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर प्रभावशील विद्युत की दर के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना में चार वर्षों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3236.59

करोड़ रूपए की छूट दी जा चुकी है। इसी तरह कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को तीन अश्वशक्ति तक के कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट दी जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों द्वारा खेती में उपयोग की जा रही बिजली को निःशुल्क रखा गया है। हाफ बिजली बिल योजना बी.पी.एल. बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है।

पिछले चार सालों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और बी.पी.एल.बिजली कनेक्शनधारी हितग्राहियों को 1973 करोड़ रूपए से ज्यादा की छूट मिल चुकी है। साथ ही कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में 6.26 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली पर 10,400 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जा चुका है। प्रदेश में संचालित हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह की गई 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर प्रभावशील विद्युत दर की दर के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना में अब तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3236.59 करोड़ रूपए की छूट दी जा चुकी है। पिछले चार सालों में हाफ बिजली बिल योजना के उपभोक्ताओं की संख्या 25.23 लाख से बढ़कर अब 41.94 लाख हो गई है। योजना का लाभ लेने की शर्त यह है कि हाफ बिजली बिल सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के बिजली बिल की बकाया राशि शेष नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार से प्राप्त स्पोर्ट्स ग्रांट की होगी जांच

रायपुर। खेल भारत, खेलो भारत के अंतर्गत (स्पोर्ट्स ग्रांट) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त अनुदान की राशि वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक की जांच के आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिए है।

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इस मंत्रालय के द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2018 को खेल अनुदान के अंतर्गत इनडोर और आऊटडोर खेलों के खेल उपकरणों की खरीदी हेतु स्पष्ट निर्देश दिया था कि शासकीय स्कूलों में बच्चों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आयु एवं अभिरूचि के अनुसार खेलकूद सामग्री के चयन में स्थानीय स्तर पर खेले जाने

वाले पारंपरिक खेलों को समाहित किया जाए। जिन विद्यालयों के प्रांगण में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं हैं, इसके लिए उपयुक्त होगा कि ऐसे विद्यालय इंडोर गेम को ध्यान में रखकर खेल सामग्री का चयन कर उच्च गुणवत्तायुक्त खेल सामग्री का क्रय विद्यालय स्तर पर करें, जिससे सभी छात्र पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकें, लेकिन प्रदेश के कुछ अधिकारियों एवं शिक्षकों की मिलीभगत से कमीशनखोरी के चलते नियम विपरीत बिना स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति से अनुमति एंव स्वीकृति लिए प्रदेश स्तर से सामग्री क्रय कर जिलों के स्कूलों में गुणवत्ताहीन खेल सामग्री भेजा जा रहा था और जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संस्था प्रमुखों को उपयोगिता और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने दबाव बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लिप्त हैं, जिसकी लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने इस मामले में विगत तीन वर्षों से राज्य सरकार से जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई रूचि नहीं दिखाया, तो इस मामले की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई और जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल की शिकायत दिनांक 6 जनवरी 2023 को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को खेल भारत, खेलों भारत के अंतर्गत (स्पोर्ट्स ग्रांट) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त अनुदान की राशि वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

आदिवासी भारत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड भोजलाल नेताम का निधन

गरियाबंद। आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड भोजलाल नेताम का आज दिनांक 04 फरवरी 2023 को आकस्मिक निधन हो गया. 75 वर्षीय कॉमरेड नेताम ग्राम जिडार, मैनपुर, जिला गरियाबंद के निवासी थे. वे अपनी युवा अवस्था से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे. वे भारत में साम्यवादी क्रांति के समर्थक थे और एक पूर्णकालिक पेशेवर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन क्रांति के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलते हुये बिताया.पार्टी के राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड सौरा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुये कहा कि कॉमरेड नेताम का आकस्मिक निधन पार्टी एवं उनके परिवार के लिये भारी क्षति है. उनके निधन से पूरे आदिवासी क्षेत्र में शोक व्याप्त है. वे बिन्द्रानवागढ़, गरियाबंद क्षेत्र में एक वरिष्ठ वामपंथी विचारक और नेता के तौर पर लोकप्रिय थे. वे वर्ष 2016 से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार के सक्रिय राज्य कमेटी सदस्य थे. वे 2018 में बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा सीट से विधायक एवं 2019 में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे.

शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर दिलाना करें सुनिश्चितः सांसद

जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश

बिलासपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सांसद श्री अरूण साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में श्री साव ने जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत् मंजूर किये गये कामों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सहूलियत के लिए स्वीकृत किये गये विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर असंतोष प्रकट करते हुए और तेज गति से काम करने के निर्देश दिये हैं।

जनहित की योजनाओं का शत-प्रतिशत फायदा लोगों को मिलना चाहिए। बैठक में मस्तूरी विधायक श्री कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान, महापौर श्री रामशरण यादव सहित सभी जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष मौजूद थे। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। सांसद श्री साव ने एजेण्डा के अनुरूप बारीकी से योजनाओं की समीक्षा की तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा में 1 लाख 93 हजार 374 पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी किया गया है। मनरेगा के तहत् 413 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार पूरा किया है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 93 करोड़ 76 लाख रूपए का व्यय किया गया है। जिसमें मजदूरी पर 62 करोड़ 17 लाख रूपए से अधिक की राशि व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन का कार्य लोगों के लिए लाभप्रद होना चाहिए। मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने कहा। लिमतरा से करी मार्ग सहित योजना के तहत अधूरे पड़े कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना को दुरूस्त करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के स्वयं के मकान होने के सपने को साकार करने वाली योजना है। इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जायेगी। लोगों को आवास के लिए भटकना न पड़े। सांसद ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरमी के मौसम में ग्रामों में पेयजल की समस्या न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा गांवों में पेयजल की दिक्कतों का तत्परता से निराकरण के निर्देश दिये गये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संचालित कामों की ठीक से मॉनीटरिंग करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिये गये।

भूपेश बघेल का 23 का फेर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023 का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने करीब एक साल से बिसात बिछानी शुरू कर दी है , साथ ही भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं। अब उन्होंने अपने काफिले में 0023 नंबर वाली गाड़ियां भी शामिल की हैं। भूपेश बघेल का जन्मदिन 23 अगस्त 1961 है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में सीजी 02 -बी बी 0023 टोयटा की काले रंग की फार्चूनर नजर आएंगी। चुनावी साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह ने 0004 नंबर की ब्लैक पजेरो गाड़ियों को अपने काफिले में शामिल किया था। डॉ रमनसिंह तीन बार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। चौथी बार सत्ता में वापसी करनी थी , लेकिन नई गाड़ियां शुभ नहीं हुईं। भाजपा 15 सीटों से ऊपर नहीं जा सकी। चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गाड़ियां बदली है। ये गाड़ियां कितनी शुभ होती हैं, यह दिसंबर 2023 में ही पता चलेगा। संभावना है कि राज्य में नवंबर 2023 में मतदान और दिसंबर 2023 में नतीजे आएंगे।

निरंजन दास ही बने रहेंगे एक्साइज कमिश्नर ?

भूपेश बघेल की सरकार ने 31 जनवरी को रिटायरमेंट के बाद 2003 बैच के प्रमोटी आईएएस निरंजन दास को संविदा नियुक्ति दे दी है। फिलहाल उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। यह नान कैडर पोस्ट है। रिटायरमेंट के पहले तक निरंजन दास के पास एक्साइज कमिश्नर और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक का प्रभार था। इन दोनों पदों पर सरकार ने अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की है , इस कारण माना जा रहा है कि ये दोनों पद निरंजन दास के पास ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार अपने विश्वस्त और टेस्टेड अफसर को ही एक्साइज कमिश्नर बना कर रखेगी । वैसे कहते हैं एक्साइज कमिश्नर बनने के लिए कई आईएएस जोड़तोड़ में लगे थे। राज्य में अब सेंविदा वाले तीन आईएएस हो गए हैं। डॉ आलोक शुक्ला स्कूल और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव और डी डी सिंह मुख्यमंत्री के सचिव के साथ सामान्य प्रशासन विभाग और आदिमजाति कल्याण के सचिव हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

विवेक ढांड को नया पद

भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को 'छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विवेक ढांड साहब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को सुझाव देंगे। श्री ढांड काफी अनुभवी और वरिष्ठ हैं , उनके अनुभव से सरकार का प्रशासनिक सिस्टम सुधर जाए , यह तो बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि आजकल प्रशासनिक सिस्टम व्हाट्सप से चल रहा है। एक जमाना था जब कलेक्टर से लेकर जिले का हर छोटा अफसर फील्ड में दौड़ता था , तब जिले का आकार भी बड़ा था। तब का एक जिला अब 4 से 6 जिले बन गए हैं। अजीत जोगी और डॉ रमन सिंह के राज में भी प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। अजीत जोगी ने पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार को और डॉ रमन सिंह ने सुयोग्य कुमार मिश्रा को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। कहते हैं आयोग का न तो कोई रिपोर्ट आया और न ही कुछ सुधार दिखा। अब देखते हैं ढांड साहब कैसे प्रशासनिक सुधार करते हैं ?

प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष के जलवे

वैसे तो संगठन में उपाध्यक्ष के पद को शोभायमान माना जाता है, लेकिन कहते हैं प्रदेश भाजपा में एक उपाध्यक्ष की तूती बोल रही है। कहा जा रहा है संगठन महामंत्री पवन साय एक बार अध्यक्ष की बात नहीं मानते, पर उपाध्यक्ष की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। उपाध्यक्ष जो चाहते हैं,वैसा कहते हैं संगठन मंत्री से काम करवा लेते हैं। इसको लेकर पार्टी में असंतोष भी उभरने लगा है। उपाध्यक्ष महोदय पहले प्रदेश भाजपा के महामंत्री थे। विरोध के कारण उन्हें हटाकर उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन पद बदला पर पावर यथावत बना रहा। उपाध्यक्ष की सलाह पर जिलों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय को राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं ने सिफारिश भी की थी। यह अलग बात है कि सिफारिश पर अमल नहीं हुआ।

उद्योग विभाग के अफसर को तलाशते उद्योगपति

कहते हैं उद्योगपति उद्योग विभाग के एक अफसर को मोबवत्ती लेकर तलाश रहे हैं। अधिकारी की मूल पदस्थापना तो उद्योग विभाग में हैं, पर सरकार ने उन्हें दोहरा चार्ज दे रखा है। दोहरे चार्ज वाले आफिस में अफसर ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि वहां मालमत्ता कुछ ज्यादा है। उद्योग विभाग में अधिकारी महोदय कब आते हैं कब चले जाते हैं ,हवा ही नहीं लगती। उद्योगपति अफसर को उद्योग विभाग में तलाश करते रह जाते हैं। कहा जाता है अफसर के उद्योग विभाग में लगातार नहीं बैठने और उद्योपतियों से न मिलने के कारण जमीन आबंटन और दूसरे मामले लगातार पेंडिग हो रहे हैं। उद्योग विभाग में ही उद्योगपतियों को भटकना पड़े तो फिर राज्य में औद्योगिक विकास कैसा होगा। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

अंबिका सिंहदेव सुर्खियों में

पति के आरोपों के कारण बैकुंठपुर की कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव श्रीमती अंबिका सिंहदेव सुर्खियों में हैं। कोरिया कुमार के नाम से प्रसिद्ध और छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्तमंत्री रामचंद्र सिंहदेव की भतीजी अंबिका सिंहदेव ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और विधायकी मिल गई। कहते हैं अंबिका को टी एस सिंहदेव के चलते टिकट मिली। कोलकाता निवासी पति ने उन्हें पहले राजनीति त्यागने की सलाह दी , फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसके चलते राज्य की राजनीति और उनके विधानसभा में नई बहस शुरू हो गई है और पारिवारिक मसला राजनीतिक रंग लेने लगा है। समय बताएगा अंबिका सिंहदेव राजनीति को प्राथमिकता देतीं हैं या परिवार को।

एक आईएएस के चुनाव लड़ने की चर्चा

राज्य के एक आईएएस के चुनाव लड़ने की चर्चा बाजार में गर्म है। कहते हैं वे कुछ महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। 2023 के चुनाव में आदिवासी इलाके के किसी सीट से भाग्य आजमाना चाहते हैं। कांकेर के विधायक शिशुपाल सोरी प्रशासनिक सेवा से रिटयरमेंट के बाद राजनीति में भाग्य आजमाया और सफल हो गए। विधायक किस्मतलाल नन्द पुलिस की सेवा के बाद राजनीति में आए। रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों- कर्मचारियों का राजनीति की राह पकड़ना कोई नई बात नहीं है। कहा जा रहा है रिटायरमेंट से पहले आईएएस अफसर साहब अपनी जमीन तैयार करने में लग गए हैं।

रायपुर। पूर्णिमा की पूर्व संध्या में श्री राष्ट्रीय करणी सेना छत्तीसगढ़ द्वारा रविवार को करणी सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह तोमर के आह्वान पर बनारस की ही तर्ज पर खारुन गंगा मैया एवं हटकेश्वर महादेव की महाआरती की जाएगी। वीरेंद्र तोमर ने बताया कि करणी सेना के द्वारा अब तक दो बार पूर्णिमा के अवसर पर खारुन गंगा मैया व हटकेश्वर महादेव की महाआरती की जा चुकी है और 5 फरवरी, रविवार को तीसरी बार संध्या 5 बजे महाआरती की जाएगी। श्री तोमर ने बताया कि बनारस की ही तर्ज पर अब महादेव घाट रायपुर में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा जिससे न सिर्फ सनातन चेतना का विकास होगा वरन् हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों में एकता का भाव भी जागृत होगा जो समाज को प्रगति की नई दिशा प्रदान करने में सहायक साबित होगा।

आदिवासी हितैषी नीतियों से बौखलाई कांग्रेस - भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की टीका टिप्पणी के संदर्भ में आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, राष्ट्रहित की नीतियों को लागू करने के कारण भाजपा को मिल रहे अपार जनसमर्थन से कांग्रेस का विनाश हो रहा है। वह सिमटकर तीन राज्यों में ही सत्ता में रह गई है। देश के विकास और अपने विनाश से कांग्रेस बौखला गई है उसके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है कि वह बचेगी अथवा गांधी जी की इच्छा को जनता पूरी कर देगी, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस आचरण से तो भ्रष्ट हमेशा से रही है अब मानसिकता से भी पथभ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे इसलिए कांग्रेस के नेता बार-बार राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। आदिवासियों से नफरत के चलते कांग्रेस के सांसद खुद को राष्ट्रपति पर भी टिप्पणी करने से रोक नहीं पाए। यही कारण है कि इतिहास में पहली बार बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आधारहीन टिप्पणी करके राष्ट्रपति को अपमानित करने की धृष्टता कांग्रेस ने की। उनके अभिभाषण को राजनीति से प्रेरित बताया।

जब राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने छत्तीसगढ़ आयी तो किसी भी कांग्रेसी नेता ने उनसे मिलने की जरूरत भी महसूस नहीं की। आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति न बने इसके लिए कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जो खुद उनकी पार्टी का नेता नहीं था और एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति न बन पाए इसके लिए पूरी ताकत लगाई। जब द्रौपदी मुर्मू जी ऐतिहासिक बहुमत से विजयी होकर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गईं तब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अधीरता इतनी निम्नता पर उतर गई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कहा गया। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज की बेटी महामहिम राज्यपाल महोदया पर लगातार अनर्गल टिप्पणी करके उनको नीचा दिखाने का काम कांग्रेसियों द्वारा लगातार किया जा रहा है।

भाजपा आदतन आदिवासी विरोधी-कांग्रेस

भाजपा की पत्रकार वार्ता पर पलटवार करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार द्वारा लिखित दस्तावेज होता जिसका परंपरागत रूप से राष्ट्रपति पठन करते है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में टीका टिप्पणी संसदीय परंपरा का हिस्सा रहा है। विपक्ष जिन बिंदुओं से असहमत होता है उस पर टिपपणी करता है। भाजपा इसको आदिवासी राष्ट्रपति से जोड़कर संसद, संविधान और राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। भाजपा का चरित्र ही आदिवासी विरोधी है। भाजपा आदतन आदिवासी विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आदिवासियों को लंगोट में रखने का षड्यंत्र तो भाजपा ने रखा था। भाजपा कभी नहीं चाहती कि आदिवासी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बने। भाजपा आदिवासियों को उनकी संस्कृति को हमेशा से दमन करना चाहती है। भाजपा यदि आदिवासियों का हित चाहती तो अभी तक आदिवासी समाज का आरक्षण बिल राजभवन में अटका नहीं होता।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

अडानी के हेराफेरी, लूट के षड़यंत्र और फर्जीवाड़े पर मोदी मौन क्यों- कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि हिंडेनबर्ग खुलासे के सप्ताह भर से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना कोई एफआईआर, ना किसी भी तरह की जांच का आदेश? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में उजागर आर्थिक अनियमितता, मनी लांड्रिंग, ब्लैक मनी और विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां बनाकर किए जा रहे हैं फर्जीवाड़े पर भाजपा और मोदी सरकार को भी भागीदार है। अडानी से भाजपा को सपोर्ट मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है और इसीलिए अडानी को बचाने उसके फर्जीवाड़े पर मोदी सरकार पर्दा डाल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि विगत 7 दिन में 120 मिलियन डॉलर अर्थात 10 लाख् करोड़ से अधिक आम जनता के मेहनत का पैसा डूब गया है, देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकारी बैंकों से अडानी को अनुपातहीन लोन किस के दबाव में दिया गया? षड्यंत्र उजागर होने के बाद भी एलआईसी का पैसा क्यों दबाव पूर्वक अडानी की कंपनी में लगवाया जा रहा है?

हम सभी को रामचरितमानस के मूल तत्व को समझना होगा-भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अब देशभर में रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान में कूद पड़े हैं। इस मसले पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया और सवाल भी पूछे। सीएम बघेल ने कहा की भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर सिर्फ राजनीति का रही हैं। जब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस फाड़ा जा रहा था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? सीएम बघेल ने दो टूक कहा की इस मामले पर भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया की कितने भाजपाई है जो अपने माता-पिता के पैर छूते हैं? रामचरितमानस पर मचे घमासान पर भूपेश बघेल ने कहा की इस मुद्दे पर बहस करना गलत है। हम सभी को रामचरितमानस के मूल तत्व को समझना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण की बात है, राम की बात है, राम को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, चाहे ही वे मरा-मरा' कहें, वे राम-राम कहने लगें क्या फर्क पड़ता है? आगे कहा कि रामचरितमानस के सकारात्मक पहलू हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। %डिबेट करना गलत है। वहां जो अच्छी चीजें हैं उन्हें स्वीकार करें। किताब से दो-चार चौपायों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके मूल तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है।

बिना भ्रष्टाचार के कांग्रेस सरकार कोई कार्य नहीं करती है - विजय शर्मा

रायपुर। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने मोटा अनाज (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया और फिर उनके प्रयास से ही 2023 विश्व अंतराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया ताकि उत्पादक इससे प्रेरित हो व उत्पादन करने वाले को लाभ मिले। विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इस प्रयास के पीछे भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को 'जन आंदोलन' बनाने की सोच थी। भारत में एशिया का लगभग 80 प्रतिशत और विश्व का 20 प्रतिशत मोटा अनाज पैदा होता है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मात्रा में मोटे अनाज का उत्पादन होता है केंद्र सरकार की योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा और इस हेतु केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को मदद कर रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बिना भ्रष्टाचार के कोई कार्य नहीं करती है यह एक बार फिर से साबित हो गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 17 से 19 फरवरी तक मिलेट्स कार्निवाल का आयोजन करने जा रही है और इस आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को दी गई है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली ऐतिहासिक निर्णय: अमरजीत भगत

रायपुर। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी और जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर राज्य की प्रगति के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। मंत्री श्री भगत आज नया रायपुर इंद्रावती भवन स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर में राजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के तत्वावधान में आयोजित नववर्ष मिलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मंत्री श्री भगत ने नवा रायपुर प्रीमियम लीग टुर्नामेंट प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवम् एनपीएल आयोजन समिति के संयोजक कमल वर्मा ने अपने उद्बोधन में आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2022 में शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने एवम् 16 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने पर सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति दूर करने, सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता एवम् चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने की मांग खाद्य मंत्री के समक्ष रखी।

कांग्रेस सरकार ने खोजे लूट के नये तरीके - अमर अग्रवाल

रायपुर। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार को लूटमार गिरोह करार देते हुए कहा है कि यह लुटेरी सरकार छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रही है। नए नए हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 25000 नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको ठेकेदार के बजाय नगरीय निकाय सीधा भुगतान करें। इसके साथ ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अनुसार इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ये अनियमित कर्मचारी सवा चार साल से नियमितीकरण का वादा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि इन अनियमित कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सबसे विचित्र स्थिति यह है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार के नये तरीके खोज लेते हैं। प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की माली हालत खराब है। निगम लगातार कर्ज पर चल रही हैं। 25000 नगर निगम प्लेसमेंट कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान होता है परंतु अधिकतर स्थानों पर ठेका के माध्यम से 16 से 17000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। नगर निगम इनकी मांगों को मानते हुए उन्हें सीधे भुगतान करने लगे तो प्रतिमाह निगम को 17 से 18 करोड़ रुपए बचेगा।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय के शोधार्थी के शोध पत्र को उत्कृष्ट पुरस्कार

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के शोधार्थी चंद्रेश चौधरी और विनोद सांवत को मैट्स यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट शोध पत्र वाचन के लिए पुरष्कृत किया गया. उन्होंने प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज से संबंधित खबरों पर शोध पत्र प्रस्तुत किया. गौरतलब है कि मैट्स यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग द्वारा तृतीय लिंग विमर्श: कल, आज और कल विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम में शोध पत्र प्रस्तुति के लिए चार सत्रों का आयोजन किया गया था. उत्कृष्ट शोध पत्रों के लिए चंद्रेश चौधरी और विनोद सावंत को जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शाहिद अली एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. राजेंद्र मोहंती ने बधाई एवं शुभकामनायें दी।

डॉ. अली ने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह से हमारे शोधार्थी समाज के उपयोगी विषयों पर शोध कार्य करते रहेंगे. साथ ही मैट्स विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. रेशमा अंसारी ने भी इस उपलब्धि के लिए शोधार्थियों को शुभकामनाएं दी।

कबीरदास साहेब की मानव सेवा के सीख की राह पर चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर में विश्वस्तरीय कबीर संस्थान बनाने की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज खरसिया में पंथश्री हुजूर मुकुंदमणिनाम साहेब स्मृति महोत्सव एवं एकोत्तरी चौका आरती महायज्ञ में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संस्थान का निर्माण करेंगे, जहां एक ही स्थान पर कबीर स्मारक के साथ संग्रहालय और शोध पीठ भी होगा। कार्यक्रम कबीर पंथ के गुरु पं हुजूर अर्धनाम साहेब जी, आचार्य, श्री कबीर धर्म स्थान ट्रस्ट खरसिया व श्री धर्माधिकारी साहेब की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल, विधायक डोंगरगांव श्री दलेश्वर साहू, श्री संदीप साहू, अध्यक्ष तेलघानी बोर्ड भी सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि कबीर साहेब ने आज से 600 साल पहले जो सीख दी है वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और समाज को दिशा दिखाने वाली है, इसलिए आज उनके मानने वाले देश-विदेश में फैले हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुओं का हमारे जीवन में ईश्वर के समकक्ष स्थान होता है। कबीरदास जी ने स्वयं अपने दोहे में कहा है कि जब गुरु और गोविंद (ईश्वर) दोनों एक साथ मिले तो पहले गुरुओं के चरण स्पर्श करें क्योंकि उन्होंने ही हमारा ईश्वर से परिचय करवाया है। जब तक गुरुओं का आशीष न मिले, मोक्ष नहीं मिल सकता है। कबीरदास जी ने समाज के पाखंड और विकृतियों को अपनी वाणी से दूर करने का कार्य किया और सरल जीवन व्यतीत करने की राह दिखाई। छत्तीसगढ़ में कबीर को मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी को साथ लेकर चलने की सीख दी।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए योजनाएं बना और संचालित कर रही हैं। किसानों, श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण का काम बड़े पैमाने कर होता है। इसको देखते हुए प्रदेश में 65 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक प्रदेश बन गया है। देश के कुल संग्रहण का 74 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से ही हो रहा है। किसानों को उनके फसलों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। इस साल धान की रिकार्ड तोड़ खरीदी की गयी है। गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी कर उससे वर्मी कम्पोस्ट और अब पेन्ट भी बनाया जा रहा है।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.